रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGD No. D.(D.)73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 14, 1979/आषाढ़ 23, 1901

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 14, 1979/ASADHA 23, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 24 मई, 1979

का०आ० 2342.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए हरियाणा विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 50-सफीदों निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हुकम सिंह, गांव कलावती, तह० सफीदों, जीन्द (हरियाणा) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हुकम सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० हरि०वि०स०/50/77]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 24th May, 1979

S.O. 2342.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hukam Singh, Village Kalawati, Tehsil Safidon, Jind (Haryana) a contesting candidate for general election to Haryana Legislative Assembly held in June, 1977 from 50-Safidon constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said

Shri Hukam Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HN-LA/50/77]

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून 1979

का०आ० 2343.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 18-समालका निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम चन्द्र उर्फ जंगली, जनता ढाबा, जी०टी० रोड समा लखा मण्डी तह० पानीपत (हरियाणा) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रामचन्द्र उर्फ जंगली को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० हरि०वि०स०/18/77]

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1979

S.O. 2343.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Chander Alias Jangli, Janta Dhaba, G.T. Road, Samalkha Mandi, Tehsil Panipat (Haryana) a contesting candidate for general election to the Haryana Legislative Assembly held in June, 1977 from 18-Sambhalka constituency, has failed to lodge an accoun of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1952, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Chander Alias Jangli to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HN-LA/18/77]

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 1979

का०आ० 2344.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 24-सूरजगढ़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राधेश्याम, वार्ड नं० 7, डाकखाना, चिड़ावा, जिला झुनझुनू, राजस्थान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राधेश्याम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज०वि०स०/24/77-(16)]

ORDER

New Delhi, the 5th June, 1979

S.O. 2344.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Radhey Shyam, Ward No. 7, Post Office Chirawa, District Jhunjhunu, Rajasthan a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 24-Surajgarh Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Radhya Shyam to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. RJ-LA/24/77 (16)]

आदेश

नई दिल्ली 6 जून, 1979

का०आ० 2345.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 5-संगरिया निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुरजा राम पुत्र श्री राम किशन जाट, सा० डीनगढ़ तहसील-संगरिया, राजस्थान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुरजा राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज०वि०स०/5/77(17)]

ORDER

New Delhi, the 6th June, 1979

S.O. 2345.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Surja Ram S/o Shri Ram Kishan Jat, Village Deengarh, Tehsil Sangaria, Rajasthan a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 5-Sangaria constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and

the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Surja Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/5/77 (17)]

आदेश

का०आ० 2346.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 5-संगरिया निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मामराज पुत्र मनीराम, सा० लाधूवाला, राजस्थान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मामराज को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज०वि०स०/5/77(18)]

ORDER

S.O. 2346.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mam Raj S/o Mani Ram, Village Ladhuwala, Rajasthan a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 5-Sangaria constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mam Raj to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. RJ-LA/5/77 (18)]

आदेश

का०आ० 2347.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 2-नोहर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बचना राम पुत्र श्री बूजन राम, वार्ड नं० 1, नोहर, राजस्थान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित रूप के अक्षर तथा रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बचना राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज०वि०स०/2/77(19)]

ORDER

S.O. 2347.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bachna Ram S/o Shri Bujan Ram, Ward No. 1, Nohar, Rajasthan a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 2-Nohar constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ;

And whereas after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bachna Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/2/77 (19)]

आदेश

का०आ० 2348.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 2-नोहर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बाबूराम पुत्र श्री नेतराम, ग्राम चकसरदारपुर, तहसील-नोहर, राजस्थान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बाबूराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद्, के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज०वि०स०/2/77(20)]

ORDER

S.O. 2348.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Babu Ram S/o Shri Neta Ram, Village Chak, Sardarpura. Tehsil Nohar, Rajasthan a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 2-Nohar constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Babu Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/2/77 (20)]

आदेश

नई दिल्ली 7 जून, 1979

का०आ० 2349—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 44-बनीपार्क निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नाथूलाल वर्मा, सोपखाना देश, चांदपोल गेट, जयपुर, राजस्थान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नाथूलाल वर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज०वि०स०/44/77(21)]

ORDER

New Delhi, the 7th June, 1979

S.O. 2349.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nathu Lal Verma, Topkhana Desh, Chandpole Gate, Jaipur, Rajasthan a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 44 Banipark constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nathu Lal Verma to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/44/77 (21)]

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 1979

का०आ० 2350.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 55-बैराठ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री घीसालाल सेपट, ढाणी सेपटावाली, तनधवली, तहसील-विराटनगर, राजस्था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री घीसालाल सेपट को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज०वि०स०/55/77(22)]

ORDER

New Delhi, the 8th June, 1979

S.O. 2350.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ghisa Lal Sapat, Dhani Sapatawali, Tan Dholi, Teh. Virath Nagar, Rajasthan. a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 55-Bairath constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ghisa Lal Sapat to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/55/77 (22)]

आदेश

नई दिल्ली, 12 जून, 1979

का०आ० 2351.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में राजस्थान में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 36-खण्डेला निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम निवास, ग्राम दुलेहपुरा, पोस्ट होड़, वाया खण्डेला, जिला सीकर (राजस्थान), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम निवास को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज० वि०स०/36/77(25)]

ORDER

New Delhi, the 12th June, 1979

S.O. 2351.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Niwas, Village Dulehpura, P. O. Hod, Via Khandela, District Sikar (Rajasthan) a contesting candidate for general election in the State of Rajasthan to Legislative Assembly held in June, 1977 from 36-Khandela constituency,

has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said cadidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Niwas to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a state for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/36/77 (25)]

आदेश

का०आ० 2352—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में राजस्थान में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 37—नीम का थाना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम सिंह, ग्राम व पोस्ट पाटन, जिला सीकर (राजस्थान) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० राज० वि०स०/37/77(26)]

ORDER

S.O. 2352.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Singh, Village and P. O. Patan District Sikar (Rajasthan) a contesting candidate for general election in the Rajasthan State Legislative Assembly held in June, 1977 from 37-Neemkathana constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/37/77 (26)]

आदेश

नई दिल्ली, 13 जून, 1979

का०आ० 2353.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में राजस्थान में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 155—जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रणजीत सिंह, ग्राम लोहारी कलां, तहसील जहाजपुर (राजस्थान), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रणजीत सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० राज० वि०स०/155/77(23)]

ORDER

New Delhi, the 13th June, 1979

S.O. 2353.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ranjit Singh, Village Lohari Kallan, Jahajpur (Rajasthan), a contesting candidate for general election in the Rajasthan State Legislative Assembly held in June, 1977 from 155-Jahazpur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ranjit Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a state for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/155/77 (23)]

आदेश

का०आ० 2354.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में राजस्थान में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 176—पचपदरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सूरा, असाड़ा, जिला बाड़मेर (राजस्थान), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सूरा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० राज० वि०स०/176/77(24)]

ORDER

S.O. 2354.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sura, Asada, District Barmer, (Rajasthan), a contesting candidate for general election in the State of Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 176-Pachpadra constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sura to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/176/77(24)]

आदेश

नई दिल्ली, 14 जून, 1979

का०आ० 2355.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि सितम्बर, 1978 में हुए केरल राज्य विधान सभा के लिए उप निर्वाचन के लिए 136-त्रिवेन्द्रम पूर्व सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एम० एस० अबदीन टी०सी० 39/1667 एम०वी० हाउस, चलाई, त्रिवेन्द्रम (केरल राज्य), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ।

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एम० एस० अबदीन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० केरल वि०स०/136/78(उप)]

ORDER

New Delhi, the 14th June, 1979

S.O. 2355.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri M. S. Abdeen, T.C. 39/1667, M. V. House, Chalai, Trivandrum (Kerala State), a contesting candidate for Bye-election to the Kerala Legislative Assembly held in September, 1978 from 136-Trivandrum (East) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri M. S. Abdeen to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/136/78(Bye)]

आदेश

नई दिल्ली, 15 जून, 1979

का०आ० 2356.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 39-आमेर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जगदीश प्रसाद, रुन्दाल वाया चोमू समोद, तहसील जामवारामगढ़, जयपुर, राजस्थान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ।

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जगदीश प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज० वि० स०/39/77(27)]

ORDER

New Delhi, the 15th June, 1979

S.O. 2356.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jagdish Prasad, Rundal Via Chomu Samod, Tehsil Jamwaramgarh, Jaipur, Rajasthan, a contesting candidate for general election to the Rajasthan State Legislative Assembly held in June, 1977 from 39-Amber constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, thereore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jagdish Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/39/77(27)]

आदेश

का० आ० 2357.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 39-आमेर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री प्रभाती लाल, ग्राम चोप, तहसील जामवारामगढ़, डाकखाना बागवाड़ा, राजस्थान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है।

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री प्रभाती लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज० वि० स०/49/77(28)]

ORDER

S.O. 2357.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Prabhati Lal, Village Chop, Tahsil Jamwa Ramgarh, Post Bagwada, Rajasthan, a contesting candidate for general election to the Rajasthan State Legislative Assembly held in June, 1977 from 39-Amber constituency, has failed to lodge

an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, thereore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Prabhati Lal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RP-LA/39/77(28)]

आदेश

का०आ० 2358.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 39-आमेर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रतन, सिरसी, तहसील जयपुर, राजस्थान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रतन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज० वि० स०/39/77(29)]

ORDER

S.O. 2358.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ratan, Sirsi, Tehsil Jaipur, Rajasthan, a contesting candidate for general election to the Rajasthan State Legislative Assembly held in June, 1977 from 39-Amber constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, thereore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ratan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/39/77(29)]

आदेश

नई दिल्ली, 21 जून, 1979

का०आ० 2359.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 20-चुरू निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लाल खां, मदीना मस्जिद के पास, आथुणा मोहल्ला, चुरू (राजस्थान), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री लाल खां को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० रा० वि० स०/20/77(30)]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 21st June, 1979

S.O. 2359.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Lal Khan, near Madina Masjid, Athuna Mohalla, Churu, Rajasthan, a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 20-Churu constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, thereore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Lal Khan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/20/77(30)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 15 जून, 1979

का०आ० 2360.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि अप्रैल, 1978 में हुए लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन के लिए 3-करनाल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विनोद कुमार, मकान नं० 2, ब्लाक नं० 3-ए, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री विनोद कुमार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० हरि० लो० स०/3/78 (उप)]

I cn-21140
9/10/80

ORDER

New Delhi, the 15th June, 1979

S.O 2360.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Vinod Kumar, House No. 2, Block No. 3A, Vishnu Garden, New Delhi, a contesting candidate for bye-election to the House of the People held in April, 1978 from 3-Karnal constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vinod Kumar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HN-HP/3/78(Bye)]

आदेश

का०आ० 2361.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए हरियाणा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 70-बरवाला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दाता राम, ग्राम व पत्रालय बरवाला, जिला हिसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण का न्यायोचित्य नही है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दाता राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० हरि० वि० स० 70/77]

आर० डी० शर्मा, अवर सचिव

ORDER

S.O. 2361.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Data Ram, Village Barwala, P.O. Barwala, District Hissar, a contesting candidate for general election to the Haryana Legislative Assembly held in June, 1977 from 70-Barwala constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, thereore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Data Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HN-LA/70/77]

R. D. SHARMA, Under Secy

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नोटिस

नई दिल्ली, 25 जून, 1979

का०आ० 2362.—इसके द्वारा, लेख्य प्रमाण नियम (नोटेरीज रूल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है, कि उक्त प्राधिकारी को श्री करनैल सिंह बरार, एडवोकेट सिविल कोर्टस, मोगा, डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट, पंजाब ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, मोगा में लेख्य प्रमाणक (नोटेरी) का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र भेजा है ।

उक्त व्यक्ति को लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियां हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिखकर भेज दिये जायें ।

[संख्या 22/35/79—न्याय]

ल० द० हिन्दी, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

NOTICE

New Delhi, the 25th June, 1979

S.O. 2362.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Karnail Singh Brar, Advocate Civil Courts, Moga, District Faridkot, Punjab for appointment as a Notary to practise in Moga.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/35/79-Jus]

L. D. HINDI, Competent Authority

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 26 जून, 1979

का०आ० 2363.—1978 के अधिनियम सं० 45 के अधीन यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा दिल्ली तथा नई दिल्ली में विचारण, अपीलीय तथा पुनरीक्षा न्यायालयों में निम्नलिखित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के मामलों में अभियोजन तथा उनसे उत्पन्न किसी अन्य मामले का भी संचालन करने के लिए बम्बई के अधिवक्ता श्री एस० बी० जयसिंघानी को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है :—

क्रम सं०	मामलों का विवरण
1	2
1	श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा अन्यों के विरुद्ध नियमित मामला सं० 1/78—एस०आई०यू० (एस०आई०बी०—I)
2	श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा अन्यों के विरुद्ध नियमित मामला सं० 1/78—एस०आई०यू० (एस०आई०बी० III)
3	श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा अन्यों के विरुद्ध नियमित मामला सं० 2/78—एस०आई०यू० (एस०आई०बी०—I)

1	2
4.	श्री संजय गांधी तथा अन्यों के विरुद्ध नियमित मामला सं० 2/78—एस०आई०यू० (एस०आई०बी०—II)
5.	श्री वी० सी० शुक्ल के विरुद्ध नियमित मामला सं० 1/78—एस०आई०यू० (एस०आई०बी०—II)

[सं० 225/23/79—ए०वी०डी० II]

टी० के० सुब्रामणियन, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 26th June, 1979

S.O. 2363.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) as amended under Act No. 45 of 1978, the Central Government hereby appoints Shri S. B. Jaisinghani, Advocate, Bombay as a Special Public Prosecutor for conducting the prosecution and also any other matter arising out of the Delhi Special Police Establishment cases mentioned below in the trial, appellate and revisional courts in Delhi and New Delhi.

Serial No.	Particulars of cases
1.	Regular case No. 1/78-SIU(SIB. I) against Smt. Indira Gandhi and others.
2.	Regular case No. 1/78-SIU (SIB. III) against Smt. Indira Gandhi and others.
3.	Regular case No. 2/78-SIU (SIB. I) against Smt. Indira Gandhi and others.
4.	Regular case No. 2/78-SIU (SIB. II) against Shri Sanjay Gandhi and others.
5.	Regular case No. 1/78-SIU. (SIB. II) against Shri V. C. Shukla.

[No. 225/23/79-AVD. II]

T. K. SUBRAMANIAN, Under Secy.

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 25 जून, 1979

का०आ० 2364.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित विभाग को जिसके कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग)।

[सं० 12022/1/78-रा०भा० (ख-2)]

हरिबाबू कंसल, उप-सचिव

(Department of Official Language)

Ne Delhi, the 25th June, 1979

S.O. 2364.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following Department, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :

Ministry of Energy (Department of Power).

[No. 12022/1/78-O.L. (B-2)]

H. B. KANSAL, Dy. Secy.

317 GI/79—2

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1979

स्टाम्प

का०आ० 2365.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम, बम्बई को प्रोमिसरी नोटों के रूप में उक्त निगम द्वारा जारी किये जाने वाले बारह करोड़, सड़सठ लाख और पन्द्रह हजार रुपये अंकित मूल्य के ए०आर०डी०सी० बंधपत्रों, 1988 (तेहरवीं शृंखला) पर स्टाम्प शुल्क के मद्दे प्रभार्य केवल बारह लाख, सड़सठ हजार एक सौ पचास रुपये के समेकित स्टाम्प शुल्क को संदाय करने की अनुज्ञा देती है।

[सं० 21/79-स्टाम्प फा०सं० 33/33/79-वि०क०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 3rd July, 1979

STAMPS

S.O. 2365.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Agricultural Refinance and Development Corporation, Bombay to pay consolidated stamp duty of twelve lakhs, sixty seven thousand, one hundred and fifty rupees only, chargeable on account of the stamp duty on A.R.D.C. Bonds, 1988 (Thirteenth series) in the form of promissory notes of the face value of twelve crores, sixty seven lakhs and fifteen thousand of rupees to be issued by the said Corporation.

[No. 21/79-Stamps-F. No. 33/33/79-ST]

का०आ० 2366.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड द्वारा अगस्त 1978 के दौरान स्टाक प्रमाण पत्रों और प्रोमिसरी नोटों के रूप में जारी किये जाने वाले एक करोड़ और दस लाख रुपये मूल्य के ऋणपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[सं० 22/79-स्टाम्प फा०सं० 33/32/79-वि०क०]

S.O. 2366.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) the Central Government hereby remits the duty with which the debentures in the form of stock certificates and promissory notes to the value of one crore and ten lakhs of rupees, raised by the Tamil Nadu Housing Board during August, 1978 are chargeable under the said Act.

[No. 22/79-Stamps-F. No. 33/32/79-ST]

का०आ० 2367.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है, जो केन्द्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रोमिसरी नोटों के रूप में जारी किये जाने वाले नौ करोड़ नब्बे लाख रुपये मूल्य के बन्धपत्रों पर, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[सं० 23/79-स्टाम्प-फा०सं० 33/5/79-वि०क०]

एन० डी० धवा, अवर सचिव

S.O. 2367.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) the Central Government hereby remits the duty with which the bond in the form of promissory notes to the value of nine crores ninety lakhs of rupees, to be issued by the National Cooperative Development Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 23/79-Stamps-F. No. 33/5/79-ST]

N. D. BATRA, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 23 जून, 1979

का०आ० 2368.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की 21 दिसम्बर, 1976 की अधिसूचना 4-136/76-ए०सी० (1) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में शब्द "जिला मंडी" के स्थान पर "जिला मंडी, कांगड़ा और कुलू" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

[संख्या 2-7/79-आर०आर०बी० (2)]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 23rd June, 1979

S.O. 2368.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (3) of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Govt. of India in the then Department of Revenue and Banking (Banking Wing) No. E. 4-136/76-AC(I), dated the 21st December, 1976, namely :—

In the said notification, for the words "district of Mandi" the words "districs of Mandi, Kangra and Kulu" shall be substituted.

[No. F. 2-7/79-RRB(2)]

का०आ० 2369.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की 21 मार्च, 1976 की अधिसूचना संख्या 4-85/75-ए०सी० (1) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में शब्द "जिला गुड़गांव" के स्थान पर "जिला गुड़गांव और महेन्द्रगढ़" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[संख्या 2-7/79-आर०आर०बी० (3)]

S.O. 2369.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (3) of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Govt. of India in the then Department of Banking No. F. 4-85/75-AC(I) dated the 26th March, 1976, namely :—

In the said notification, for the words "district of Gurgaon", the words "districts of Gurgaon and Mahandragarh" shall be substituted.

[No. F. 2-7/79-RRB(3)]

नई दिल्ली, 25 जून, 1979

का०आ० 2370.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री आर० ए० अग्रवाल को सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़ का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री आर० ए० अग्रवाल अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर०आर०बी०]

New Delhi, the 25th June, 1979

S.O. 2370.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri R. A. Agarwal as the Chairman of the Samyut Kshetriya Gramin Bank, Azamgarh and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri R. A. Agarwal shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2371.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एम० डी० प्रभु को तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, बेल्लारी का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री एम० डी० प्रभु अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर०आर०बी०]

S.O. 2371.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), The Central Government hereby appoints Shri M. D. Prabhu as the Chairman of the Tungabhadra Gramin Bank, Bellary and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri M. D. Prabhu shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2372.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री मृणाल बैश्य को प्राग-ज्योतिष गांवलिया बैंक, नलबाड़ी का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री मृणाल बैश्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर०आर०बी०]

S.O. 2372.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Mrinal Baishya as the Chairman of the Pragiyotish Gaonlia Bank, Nalberi and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri Mrinal Baishya shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2373.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री मनवेन्द्र सेन को त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतल्ला का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री मनवेन्द्र सेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[सं० एफ० 3-1/79-आर०आर०बी०]

S.O. 2373.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Manabendra Sen as the Chairman of the Tripura Gramin

Bank, Agartala and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri Manabendra Sen shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2374.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री बी० डी० नारंग को रीवा सीधी ग्रामीण बैंक, रीवा का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री बी० डी० नारंग अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3—1/79—आर०आर०बी०]

S.O. 2374.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri B. D. Narang as the Chairman of the Rewa Sidhi Gramin Bank, Rewa and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri B. D. Narang shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2375.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एन० के० सिन्हा, को वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एन० के० सिन्हा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[सं०एफ 3-1/79 आर०आर०बी]

S.O. 2375.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri N. K. Sinha as the Chairman of the Vaishali Kshetriya Gramin Bank, Muzaffarpur and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri N. K. Sinha shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2376.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एम० जे० जोशी को कच्छ ग्रामीण बैंक, भुज का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री एम० जे० जोशी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2376.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri M. J. Joshi as the Chairman of the Kutch Gramin Bank, Bhuj and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri M. J. Joshi shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79 RRB]

का०आ० 2377.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एस० एल० जैन को जयपुर-नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है। तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री एस० एल० जैन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2377.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri S. L. Jain as the Chairman of the Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank, Jaipur and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri S. L. Jain shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2378.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एस० सी० दास को कटक ग्राम्य बैंक, कटक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री एस० सी० दास अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2378.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri S. C. Dash as the Chairman of the Cuttack Gramya Bank, Cuttack and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri S. C. Dash shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2379.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री के० पी० लाल को मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री के० पी० लाल अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2379.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri K. P. Lal as the Chairman of the Monghyr Kshetriya Gramin Bank, Monghyr and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri K. P. Lal shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2380.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री बिमल चक्रवर्ती को गौड़ ग्रामीण बैंक, मालदा का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री बिमल चक्रवर्ती अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[सं० एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2380.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Bimal Chakraborty as the Chairman of the Gaur Gramin Bank, Malda and specifies the period commencing on the

1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri Bimal Chakraborty shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2381.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री प्रदीप्त भट्टाचार्य को मल्लभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री प्रदीप्त भट्टाचार्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2381.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Pradeepta Bhattacharyya as the Chairman of the Mallabhum Gramin Bank, Bankura and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri Pradeepta Bhattacharyya shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2382.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एम० वी० इनामदार को मालप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड़ का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री एम० वी० इनामदार अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2382.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri M. V. Inamdar as the Chairman of the Malaprabha Grameena Bank, Dharwar and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri M. V. Inamdar shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2383.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री टी० एम० राजशेखर को कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री टी० एम० राजशेखर अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2383.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri T. M. Rajasekhar as the Chairman of the Cauvery Grameena Bank, Mysore and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri T. M. Rajasekhar shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2384.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री बी० रामचन्द्र राव को श्री विशाखा ग्रामीण बैंक, श्रीकाकुलम का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप मे निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री बी० रामचन्द्र राव अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2384.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri B. Ramachandra Rao as the Chairman of the Sri Visakha Grameena Bank, Srikakulam and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri B. Ramachandra Rao shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2385.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री वाई० वी० सत्यनारायण मूर्ति को नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्मम का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री वाई० वी० एस० मूर्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2385.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Y. V. Satyanarayana Murthy as the Chairman of the Nagarjuna Grameena Bank, Khammam and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri Y. V. S. Murthy shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2386.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एच० एम० शारदा को बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप मे निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एच० एम० शारदा अध्यक्ष के रूप मे कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2386.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri H. M. Sharda as the Chairman of the Bilaspur-Raipur Kshetriya Gramin Bank, Bilaspur and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri H. M. Sharda shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2387.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री सी० एच० तमाकुवाला को जामनगर ग्रामीण बैंक, जामनगर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप मे निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री सी० एच० तमाकुवाला अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2387.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri C. H. Tamakuwala as the Chairman of the Jamnagar

Gramin Bank, Jamnagar and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri C. H. Tamakuwala shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1 79-RRB]

का०आ० 2388.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एम० एम० वाधवानी को बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़ का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एम० एम० वाधवानी, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2388.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri S. M. Wadhwani as the Chairman of the Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank, Tikamgarh and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri S. M. Wadhwani shall hold office as such Chairman

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2389.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० पी० गर्ग को सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुल्तानपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री एस० पी० गर्ग अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2389.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri S. P. Garg as the Chairman of the Sultanpur Kshetriya Gramin Bank, Sultanpur and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri S. P. Garg shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2390.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक 1976 अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री ए० के० शेट्टी को साऊथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मल्लपुरम का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री ए० के० शेट्टी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[सं० एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2390.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri A. K. Shetty as the Chairman of the South Malabar Gramin Bank Malappuram and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri A. K. Shetty shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2391.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री बी० बी० के० सिन्हा को रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री बी० बी० के० सिन्हा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2391.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri B. B. K. Sinha as the Chairman of the Rae-Bareli Kshetriya Gramin Bank, Rae-Bareli and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri B. B. K. Sinha shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1 '79-RRB]

का०आ० 2392.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री के० अशोक कौनी को कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री के० अशोक कौनी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2392.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri K. Ashok Kini as the Chairman of the Krishna Grameena Bank, Gulbarga and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri K. Ashok Kini shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2393.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री बी० के० घोष को संथाल परगना ग्रामीण बैंक, दुमका का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री बी० के० घोष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर०आर०बी०]

S.O. 2393.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri B. K. Ghosh as the Chairman of the Santhal Parganas Gramin Bank, Dumka and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri B. K. Ghosh shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2394.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री सी० सी० आर० कामथ को नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नानौर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री सी० सी० आर० कामथ अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर०आर०बी०]

S.O. 2394.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints

Shri C. C. R. Kamath as the Chairman of the North Malabar Gramin Bank, Cannanore and Specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri C. C. R. Kamath shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2395.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री आर० सी० बुद्धिराजा को गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री आर० सी० बुद्धिराजा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर०आर०बी०]

S.O. 2395.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri R. C. Budhiraja as the Chairman of the Gurgaon Gramin Bank, Gurgaon and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri R. C. Budhiraja shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2396.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री कृपासागर कुंडे को रायलासीमा ग्रामीण बैंक, कुडप्पा का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री कृपासागर कुंडे अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2396.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Krupasagar Kunde as the Chairman of the Rayalaseema Grameena Bank, Cuddapah and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri Krupasagar Kunde shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2397.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री दिनकर राव को प्रथमा बैंक, मुरादाबाद का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री दिनकर राव अध्यक्ष के रूप कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर०आर०बी०]

S.O. 2397.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Dinakar Rao as the Chairman of the Prathama Bank, Moradabad and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri Dinakar Rao shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2398.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार,ए तद्द्वारा श्री एम० के० खन्ना को हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री एस० के० खन्ना अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2398.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri S. K. Khanna as the Chairman of the Haryana Kshetriya Gramin Bank, Bhiwani and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri S. K. Khanna shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2399.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री पी० के० जैन को भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री पी० के० जैन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर०आर०बी०]

S.O. 2399.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri P. K. Jain, as the Chairman of the Bhojpur Rohtas Gramin Bank, Arrah and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 31st December, 1979 as the period for which the said Shri P. K. Jain shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2400.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री आर० जी० पुरी को शेखावटी ग्रामीण बैंक, सीकर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप मे निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री आर० जी० पुरी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर०आर०बी०]

S.O. 2400.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri R. G. Puri as the Chairman of the Shekhawati Gramin Bank, Sikar and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri R. G. Puri shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का०आ० 2401.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री बी० के० प्रसाद को मगध ग्रामीण बैंक, गया का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री बी० के० प्रसाद अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2401.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri B. K. Prasad as the Chairman of the Magadh Gramin

Bank, Gaya and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri B. K. Prasad shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का० आ 2402.— प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री के० एस० राजपूत को हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री के० एस० राजपूत अध्यक्ष के रूप मे कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79—आर०आर०बी०]

S.O. 2402.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Governmen hereby appoints Shri K. S. Rajput as the Chairman of the Himachal Gramin Bank, Mandi and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri K. S. Rajput shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का० आ० 2403.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री सुरेन्द्र महन्ती को पुरी ग्राम्य बैंक, पीपरी का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979, से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री सुरेन्द्र महन्ती अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं० एफ० 3-1/79—आर०आर०बी०]

S.O. 2403.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Surendra Mahanti as the Chairman of the Puri Gramya Bank, Pipli and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 31st December, 1979 as the period for which the said Shri Surendra Mahanti shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का० आ० 2404.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, अधिनियम, 1976 (1976 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री टी० आर० कल्लपीरन को, पांड्यन ग्राम बैंक, सत्तूर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री टी० आर० कल्लपीरन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79—आर०आर०बी०]

S.O. 2404.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri T. R. Kallapiran as the Chairman of the Pandyan Grama Bank, Sattur and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 31st December, 1979 as the period for which the said Shri T. R. Kallapiran shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का० आ० 2405.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री बी० पी० अग्रवाल को गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री बी० पी० अग्रवाल अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79—आर०आर०बी०]

S.O. 2405.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri B. P. Agrawal as the Chairman of the Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank, Gorakhpur and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri B. P. Agrawal shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का० आ० 2406.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एम० आर० होटा को कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक, जेपोर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री एम० आर० होटा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79—आर०आर०बी०]

S.O. 2406.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri M. R. Hota as the Chairman of the Koraput Panchabati Gramya Bank, Jeypore and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri M. R. Hota shall hold office as such Chairman.

[No. F.3-1/79-RRB]

का० आ० 2407.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री टी० आर० राव को बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलंगीर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री टी० आर० राव अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79—आर०आर०बी०]

S.O. 2407.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri T. R. Rao as the Chairman of the Bolangir Anchalik Gramya Bank, Bolangir and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri T. R. Rao shall hold office as such Chairman.

[No. F.3-1/79-RRB]

का०आ० 2408.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री सुदर्शन कुमार शर्मा को मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री सुदर्शन कुमार शर्मा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79—आर०आर०बी०]

S.O. 2408.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Sudershan Kumar Sharma as the Chairman of the

Marwar Gramin Bank, Pali and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri Sudershan Kumar Sharma shall hold office as such Chairman.

[No. F.3-1/79-RRB]

का० आ० 2409.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री ठाकुर प्रसाद सिंह को भगीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर, 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री ठाकुर प्रसाद सिंह अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79—आर०आर०बी०]

S.O. 2409.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Thakur Prasad Singh as the Chairman of the Bhagirath Gramin Bank, Sitapur and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri Thakur Prasad Singh shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का० आ० 2410.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री प्रदीप कुमार दास को उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79—आर०आर०बी०]

S.O. 2410.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Pradip Kumar Das as the Chairman of the Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri Pradip Kumar Das shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का० आ० 2411.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री राजेश्वर प्रसाद को कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री राजेश्वर प्रसाद अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर०आर०बी०]

S.O. 2411.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Rajeswar Prasad as the Chairman of the Kosi Kshetriya Gramin Bank, Purnea and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June 1982 as the period for which the said Shri Rajeswar Prasad shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का० आ० 2412.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र कुमार रस्तोगी को बाराबन्की ग्रामीण बैंक, बाराबन्की का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री ज्ञानेन्द्र कुमार रस्तोगी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79—आर०आर०बी०]

S.O. 2412.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Gyanandra Kumar Rastogi as the Chairman of the Barabanki Gramin Bank, Barabanki and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri Gyanandra Kumar Rastogi shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का० आ० 2413.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री सत्य प्रकाश शर्मा को हरदोई उन्नाव ग्रामीण बैंक हरदोई का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री सत्य प्रकाश शर्मा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79—आर०आर०बी०]

S.O. 2413.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Satya Prakash Sharma as the Chairman of the Hardoi-Unnao Gramin Bank, Hardoi and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri Satya Prakash Sharma shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का० आ० 2414.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एस० आर० शुक्ल को बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एस० आर० शुक्ल अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79—आर०आर०बी०]

S.O. 2414.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri S. R. Shukla as the Chairman of the Ballia Kshetriya Gramin Bank, Ballia and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri S. R. Shukla shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का० आ० 2415.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री शिव शर्मा को चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतिहारी का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री शिव शर्मा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर०आर०बी०]

S.O. 2415.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints

Shri Sheo Sharma as the Chairman of the Champaran Kshetriya Gramin Bank, Motihari and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri Sheo Sharma shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का० आ० 2416.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एस० के० फड़नवीस को मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नांदेड का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1980 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री एस० के० फड़नवीस अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79-आर० आर० बी०]

S.O. 2416.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri S. K. Fadnavis as the Chairman of the Marathwada Gramin Bank, Nanded and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1980 as the period for which the said Shri S. K. Fadnavis shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का० आ० 2417.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एस० आर० कोतवाल को जम्मू रूरल बैंक, जम्मू का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री एस० आर० कोतवाल अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79 आर० आर० बी०]

S.O. 2417.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri S. R. Kotwal as the Chairman of the Jammu Rural Bank Jammu and specifies the period commencing on the 1st July 1979 and ending with the 31st December, 1979 as the period for which the said Shri S. R. Kotwal shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

का० आ० 2418.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री के० के० बन्द्योपाध्याय को मयूराक्षी ग्रामीण बैंक, सूरी का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री के० के० बन्द्योपाध्याय अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 3-1/79 आर० आर० बी०]

S.O. 2418.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri K. K. Bandyopadhyay as the Chairman of the Mayurakshi Gramin Bank, Suri and specifies the period commencing on the 1st July, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri K. K. Bandyopadhyay shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]

नई दिल्ली, 27 जून, 1979

का० आ० 2419.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री गोवर्धन दास गोयल को फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक, फर्रुखाबाद का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1980 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री गोवर्धन दास गोयल अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[सं० एफ० 3-1/79-आर०आर०बी०)]
सी०आर० बिश्वास, उप-सचिव

New Delhi, the 27th June, 1979

S.O. 2419. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Goverdhan Das Goyal as the Chairman of the Farrukhabad Gramin Bank, Farrukhabad and specifies the period commencing on the 1st July,, 1979 and ending with the 30th June, 1980 as the period for which the said Shri Goverdhan Das Goyal shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB]
C. R. BISWAS, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 1 जून, 1979

का०आ० 2420.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध 25 मार्च, 1980 तक साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड, टिन्नेवेली पर तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के सेरमादेवी गांव में बैंक द्वारा धृत अचल सम्पत्ति अर्थात् कुल 19 सेंट क्षेत्रफल की सर्वे संख्या 200-7, 8 और 10 ई०एल० वाली नंजा भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे।

[सं० 15(12)-बी०ओ०/III/79]

New Delhi, the 1st June, 1979

S.O. 2420.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply up to 25th March 1980 to the South India Bank Limited, Tinnevelly in respect of the immovable property viz. Nanja Lands having Survey Numbers 200—7, 8 and 10 L measuring in all 19, cents held by it at Sermadevi village, Tirunelveli District, Tamil Nadu.

[No. 15(12)-B.O. III/79]

नई दिल्ली, 21 जून, 1979

का० आ० 2421.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध 26 मई, 1980 तक के लिये विजया बैंक लिमिटेड, बंगलौर पर निम्नलिखित अचल सम्पत्ति के बारे में लागू नहीं होंगे :—

(1) मंगलौर के कम्बला वार्ड में आर०एस० संख्या 536-1 और टी०एस० संख्या 387 वाली 30 सेंट की सम्पत्ति जिसमें मकान और बाग है ।

(2) मंगलौर के मंगलादेवी वार्ड में टी०एस० संख्या 326 (आर० एस० संख्या 599) वाली सम्पत्ति जिसमें 2 प्लाट हैं ।

(3) टी०एस० संख्या 327 (आर०एस० संख्या 598) वाली अत्तावूर सम्पत्ति जिस में 27 सेंट का बाग है ।

[संख्या 15(11)बी०ओ०-III 79)]

मे०मा० उसगांवकर, अवर सचिव

New Delhi, the 21st June, 1979

S.O. 2421.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply upto the 26th May, 1980 to the Vijaya Bank Ltd., Bangalore, in respect of the following immovable properities viz. :

(1) Property bearing R. S. No. 536-1 & T. S. No. 387 of 30 cents consisting of a house and garden in Kambla Ward, Mangalore.

(2) Property bearing T. S. No. 326 (R. S. No. 599) consisting of two vacant plots in Mangaladevi Ward, Mangalore.

(3) Attavar property bearing T. S. No. 327 (R. S. No. 598) consisting of 27 cents of garden.

[No. 15(11)-B.O. III/79]
M. B. USGAONKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 जून, 1979

का० आ० 2422.—भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा वार्षिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के उपसचिव, श्री आर० एन० बालसुब्रह्मण्यन को स्टेट बैंक आफ मैसूर के निदेशक के रूप में नामित करती है ।

[संख्या एफ० 8/4/79-बी०ओ०-I]

जे० सी० राय, निदेशक

New Delhi, the 28th June, 1979

S.O. 2422.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), the Central Government, in consultation with the State Bank of India, hereby nominates Shri N. Balasubramanian, Deputy Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi to be a Director of the State Bank of Mysore.

[No. F. 8/4/79-B.O. I]
J. C. ROY, Director

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1979

(आय-कर)

का० आ० 2423.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; समय-समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना सं० 679 [फा० सं० 187/2/74-आ० क० (ए I)], तारीख 20 जुलाई, 1974 से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है : —

क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ (1), (2) और (3) के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी : —

आय-कर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3
1. अमृतसर	अमृतसर	1. जिला I, अमृतसर 2. जिला II, अमृतसर 3. जिला III, अमृतसर 4. सम्पदा-शुल्क और आय-कर सर्किल, अमृतसर 5. गुरदास पुर 6. पठानकोट 7. श्रीनगर 8. सम्पदा-शुल्क और आय-कर सर्किल, श्रीनगर 9. जम्मू 10. बटाला

[सं० 2644 (फा० सं० 187/1/79 आ० क० (ए I)]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, 8th January, 1979

(INCOME-TAX)

S.O. 2423.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following amendments to the schedule appended to the schedule appended to its Notification No.679 [F.No.187/2/74-II (AI)] dated 20 th July, 1974 as amended from time to time :—

Existing entries under Columns (1), (2) and (3) against Sl.No. 1 shall be substituted by the following entries :—

Commissioner of Income-tax.	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1. Amritsar	Amritsar.	1. Distt. I, Amritsar. 2. Distt. II, Amritsar. 3. Distt. III, Amritsar 4. Estate-Duty-cum-Income-tax Circle, Amritsar. 5. Gurdaspur. 6. Pathankot. 7. Srinagar. 8. Estate-Duty-cum-Income-tax Circle, Srinagar. 9. Jammu. 10. Batala.

[No. 2644 (F.No. 187-1/79 II(AI)]

का० आ० 2424.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 1 (फा० सं० 55/233/63-आ० क०), तारीख 18-5-64 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्धन करता है ।

अनुसूची में, क्रम सं० 88 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा ।

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
89	भारत में कहीं भी स्थित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में प्रतिनियुक्त विदेशी तकनीशियन	आयकर अधिकारी, ए-वार्ड, उदयपुर	सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) उदयपुर रेंज, उदयपुर	सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उदयपुर रेंज उदयपुर	आय-कर आयुक्त (अपील) राजस्थान-II, जयपुर	आय-कर आयुक्त, जोधपुर

यह अधिसूचना 8-1-1979 से प्रभावी होगी ।

[सं० 2645 (फा० सं० 188/1/78-आ०क० (ए I)]

S.O. 2424.—In exercise of the powers conferred by Section 126 of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961), and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following additions to the Schedule annexed to its Notification No.1 (F.No.55/233/63-IT) dated 18-5-64 as amended from time to time.

In the Schedule after Sl.No.88 the following shall be added.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7
89.	Foreign Technicians deputed to Hindustan Zinc Ltd. Udaipur stationed anywhere in India	Income-tax Officer, A-Ward, Udaipur.	Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Udaipur Range, Udaipur.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax Udaipur Range, Udaipur.	Commissioner of Income-tax (Appeals,) Rajasthan-II, Jaipur.	Commissioner of Income-Tax, Jodhpur.

This Notification shall have effect from 8-1-1979.

[No. 2645(F.No.188/1/78-IT(AI)]

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1979

का०आ० 2425.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 679 [फा० सं० 187/2/74-आ० क० (ए I)], तारीख 20 जुलाई, 1974 से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है :

क्रम सं० 2 के सामने आन्ध्र प्रदेश-1 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

आय-कर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3
आंध्र प्रदेश-1	हैदराबाद	1 कम्पनी सर्किल, हैदराबाद ।
		2. वेतन सर्किल, हैदराबाद ।
		3 सं० शु० और आ० क० सर्किल, हैदराबाद ।
		4 स० शु० और आ० क० सर्किल, काकीनाडा ।
		5. स० शु० और आ० क० सर्किल गुन्टूर ।
		6 परियोजना सर्किल, हैदराबाद ।
		7 गुन्टुर सर्किल, गुन्टूर ।
		8 महबूब नगर सर्किल, महबूब नगर ।
		9 संगारेड्डी सर्किल, संगारेड्डी ।
		10. अनन्तपुर सर्किल, अनन्तपुर ।
		11. हिन्दूपुर सर्किल, हिन्दूपुर ।
		12. कुड्डापा सर्किल, कुड्डापा ।
		13. प्रोड्डूटूर सर्किल, प्रोड्डूटूर ।
		14. अडोनी सर्किल, अडोनी ।
		15. नांड्याल सर्किल, नांड्याल ।
		16. करनूल सर्किल, करनूल ।
		17 नालगोंडा सर्किल, (अस्थायी मुख्यालय, हैदराबाद) ।
		18. सम्पदा शुल्क और आय-कर सर्किल, अनन्तपुर ।

[सं० 2672 (फा० सं० 187/29/78-आ० क० (ए-I)]

जे० पी० शर्मा, निदेशक

New Delhi, the 20th January, 1979

S.O. 2425.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the schedule appended to its Notification No.679 [F.No.187/2/74-IT/(AI)] dated the 20th July, 1974 as amended from time to time.

The entries against Sl. No. 2, Andhra Pradesh KI, shall be substituted by the following :—

Commissioner of Income-tax	Headquarters	Jurisdiction
Andhra Pradesh-I	Hyderabad.	1. Company Circle, Hyderabad 2. Salary Circle, Hyderabad. 3. E.D.-cum-I.T. Circle, Hyderabad. 4. E.D.-cum-I.T. Circle, Kakinada. 5. E.D.-cum-I.T. Circle, Guntur. 6. Project Circle, Hyderabad· 7. Gunutur Circle, Guntur. 8. Mahaboobanagar Circle, Mahaboobnagar. 9. Sangareddy Circle, Sangareddy. 10. Anantapur Circle, Anantapur. 11. Hindupur Circle, Hindupur 12. Cuddapah Circle, Cuddapah 13. Productur Circle, Proddutur 14. Adoni Circle, Adoni. 15. Nandyal Circle, Nandyal. 16. Kurnool Circle, Kurnool. 17. Nalgonda Circle (Temp. H. Qrs. at Hyderabad). 18. Estate-duty-cum-Income-tax Circle, Anantapur.

[No. 2672(F.No. 187/29/78-IT (AI)]
J. P. SHARMA, Director

वाणिज्य नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

रद्द करने का आदेश

नई दिल्ली, 29 जून, 1979

(वाणिज्य विभाग)

का॰आ॰ 2426——सर्वश्री इंडियन डेरी कार्पोरेशन, दर्पण बिल्डिंग, आर॰ सी॰ दत्त रोड, बड़ौदा को क्रायोजेनिक उपस्करों आदि के आयात के लिए 8,20,539 रुपये के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का आयात लाइसेंस सं॰ जी/ए/1076057, दिनांक 5-11-77 प्रदान किया गया था जो जारी होने की तिथि से 24 मास के लिए वैध था। अब पार्टी ने उपर्युक्त आयात लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति प्रदान करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति उनसे अस्थानस्थ हो गई है। पार्टी ने आयात व्यापार नियमों के अनुसार एक आवश्यक शपथ-पत्र दाखिल किया है जिसके अनुसार उपर्युक्त आयात लाइसेंस कलकत्ता के सीमा-शुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत था और उसका आंशिक रूप से उपयोग हो गया था और लाइसेंस में 4,57,750/-रुपये की राशि शेष है। शपथ-पत्र में यह भी शामिल किया गया है कि आयात लाइसेंस की उक्त सीमा-शुल्क प्रति बाद में मिल गई तो वह लाइसेंस प्राधिकारियों को लौटा दी जाएगी। मैं संतुष्ट हूं कि मूल लाइसेंस (केवल सीमा-शुल्क प्रति) अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को आयात लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रति जारी की जाए। आयात लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

[मिसिल सं॰ 8 मेड-12/77-78/एम॰ एल॰ I/111]
जे॰ पी॰ सिंघल, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

MINISTRY OF COMMENCE, CIVIL SUPPLIES AND COORPERATION.

Office of the Chief Controller of Imports and Exports

Cancellation Order

New Dehi, the 29th June, 1979

(Department of Commerce)

S.O. 2426.—M/s. Indian Dairy Corporation, Darpan Building, R. C. Dutt Road, Baroda were granted an import licence No. G/A/1076057, dated 5-11-77 for a CIF Value of Rs. 8,20,539 for import Cryogenic Equipments etc. valid for 24 months from the date of issue. Now the party have applied for grant of a Duplicate Copy of customs purpose copy of the aforesaid import licence on the ground that the original one has been mispaced by them. The party has furnished necessary affidavit as per ITC Rules according to which the aforesaid import licence was registered with Calcutta Customs House and was utilised partly and the balance against the licence is Rs. 4,57,750. It has also been incorporated in the affidavit that if the said customs copy of the import licence is traced or found later on, it will be returned to the issuing authority. I am satisfied that the original licence (customs copy only) has been misplaced and direct that duplicate customs copy of the import licence should be issued to the applicant. The original customs purpose copy of the import licence is hereby cancelled.

[File No. 8/MAID-12/77-78/M.L. I/111]
J. P. SINGHAL, Dy. Chief Controller of Imports and Exports
for Chief Controller of Imports and Exports

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 1979

का॰ आ॰ 2427.—सर्वश्री मैसूर पावर कार्पोरेशन लि॰, बंगलौर को अप्रैल-मार्च 73-74 की लाइसेंसिंग अवधि के लिए रूस से 3,11,35,461 रुपये के 2× 27 5 मेगावाट जनरेटिंग प्लांट 1 सं॰ इमोटी क्रेन का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस सं॰ जी/सी/2029373/डी/एस/यू/48/एच/37-38 दिनांक 28-7-73 प्रदान किया गया था। बाद में आयात लाइसेंस का मूल्य 3,12,28,461 रुपये तक बढ़ा दिया गया था।

पार्टी ने उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क प्रति, सीमा शुल्क समाहर्ता (सीमा शुल्क सदन), मद्रास के पास पंजीकृत करवाने के बाद खो गई है और उसका आंशिक रूप से उपयोग किया गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि लाइसेंस कुल 3,12,28,461 रुपये के लिए जारी किया गया था और शेष 41,273 रुपये के लिए अनुलिपि प्रति अपेक्षित है। उन्होंने सत्यनिष्ठा पूर्वक इस बात की भी पुष्टि की है और घोषणा करते हैं कि उक्त लाइसेंस उनके द्वारा न तो रद्द किया गया है, धरोहर रखा गया है, हस्तांतरित किया गया है या उनके नाम से किसी भी उद्देश्य/विचार, चाहे जो भी हो, के लिए किसी अन्य पार्टी को दिया गया है और उन्होंने लाइसेंस रद्द करने का निवेदन किया है। यदि मूल लाइसेंस बाद में मिल जाएगा तो उन्होंने उसे हमारे रिकार्ड के लिए वापिस करने के लिए भी वचन दिया है।

आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक, 1979-80 के अध्याय 14 के पैरा 334 द्वारा यथा अपेक्षित, आवेदक ने अपने तर्क के समर्थन में नोटरी बंगलौर शहर के सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं॰ जी सी/2029373/डी/एस/यू/48/एच/37-38, दिनांक 28-7-73 की सीमा

शुल्क प्रति खो गई है और निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रति की अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जाए। लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रति रद्द कर दी गई है।

आयात लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं० सी जी 2/एचईपी (एम वाई-7)/73-74/534]

सी० एस० आर्या, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

ORDER

New Delhi, the 27th May, 1979

S.O. 2427.—M/s. Mysore Power Corporation Ltd. Bangalore have been granted Import Licence No. G/C/2029373/D/SU/48/H/38, dated 28-7-73 for Rs. 3,11,35,461 (Rupees Three crores Eleven lakhs Thirty Five thousand Four hundred and Sixty One only) for import of 2 x 27.5MW Generating Plant-1 No. EOT Crane from USSR, during the licensing period AM 73-74. The value of the import licence was later raised to Rs. 3,12,28,461.

The party now requested for issue of a duplicate Customs Purpose Copy of the above licence on the ground that the Original Customs Purpose Copy has been lost after having been registered with the Assistant Collector of Customs (Customs House), Madras and utilized partly. They have also stated that the total amount for which the licence was issued is Rs. 3, 12,28,461 only and duplicate copy now required is to cover the balance of Rs. 41,273. They have also solemnly affirmed and declared that the above said licence has not been cancelled, pledged, transferred or handed over by them on their behalf to any other party for any purpose/consideration whatsoever and have requested to cancell the licence. They have also undertake to return the original licence if traced later for our records.

In support of their contention, the applicant have filed an affidavit duly sworn in before Notary, Bangalore city as required in para 334 of Chapter XIV of Hand Book of Import-Export Procedures, 1979-80. The undersigned is satisfied that the original Customs Purpose Copy of Import Licence No. G/C/2029373/D/SU/48/H/37-38, dt. 28-7-73 has been lost and directs that duplicate copy of the Customs Purpose Copy of the licence should be issued to the applicant. The original Customs Purpose Copy of the licence has been cancelled.

The duplicate copy of Customs Purpose Copy of the Import licence is being separately.

[No. CGII/HEP(My-7)/73-74/534]

C. S. ARYA, Dy. Chief Controller of Imports & Export,

for Chief Controller of Imports & Export

(नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 25 जून, 1979

का० आ० 2428.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाण चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-3462 जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं उन्नीस अप्रैल, उन्नीस सौ उन्यासी से रद्द कर दिया गया है :

अनुसूची

क्रम सं०	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
1	2	3	4	5
1.	सी एम/एल-3462 1973-06-29	सर्वश्री केमिकल्स एण्ड इंसेक्टीसाइड्स रामनगर करंजहा रेल स्टेशन कुशमी, उत्तर पूर्वी रेलवे, गोरखपुर (उ० प्र०) इनका कार्यालय सराफ चैम्बर्स, हिन्दी बाजार, गोरखपुर (उ० प्र०) में है।	बी एच सी धूलन पाउडर ट्रेडमार्क : "सेफैक्सान"	IS : 561—1978 बी एच सी (एच सी एच) धूलन पाउडर की विशिष्ट (चतुर्थ पुनरीक्षण)

[सीएमडी/55 : 3462]

ए० पी० बनर्जी, उपमहानिदेशक

(Deptt. of Civil Supplies & Co-operation)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 25th June, 1979

S.O. 2428.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations, 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-3462 particulars of which are given below has been cancelled with effect from Nineteenth April, One Thousand Nine Hundred and Seventynine:

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	Name & Address of the Licensee	Article/Process covered by the the licensees cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	C/M/L-3462 1973-06-29	M/s. Chemicals & Insecticides, Ramnagar Karanjaha, Railway Station Kushmi, N.E. Railway, Gorakhpur (U.P.) having their Office at Saraf Chamber, Hindi Bazar, Gorakhpur (U.P.).	BHC Dusting Powders Trade Mark : 'SAFEXON'	IS : 561—1978 Specification for BHC (HCH) Dusting Powders (Fourth Revision)

[CND/55 : 3462]

A. P. BANERJI, Dy. Director General, ISI

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 26 जून, 1979

का०आ० 2429.— पैट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि के प्रयोगकर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 2 की उपधारा (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में उल्लिखित प्राधिकारी को उक्त कालम (2) की तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्रों के भीतर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिये एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है ।

अनुसूची

प्राधिकारी एवं पता	क्षेत्र
कार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकारी, इंडियन आयल कार्पोरेशन लि०, (शोधनशाला एवं पाइपलाइन प्रभाग), गोहाटी, सिलीगुरी उत्पाद पाइपलाईन, गोहाटी ।	असम राज्य

[सं० 12017/1/74-एल०एण्ड एल०/प्रोडक्शन]

एस० एम० वाई० नदीम, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Deptt. of Petroleum)

New Delhi, the 26th June, 1979

S.O.2429.—In pursuance of clause(a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby authorises the authority mentioned in column 1 of the Schedule below to perform the functions of the Competent Authority under the said Act within the areas mentioned in the corresponding entry in column 2 of the said Schedule.

SCHEDULE

Authority and Address	Areas
Personnel and Administrative Officer, Indian Oil Corporation Limited, (Refineries and Pipelines Division), Gauhati, Siliguri Product Pipeline, Gauhati.	State of Assam

[No.12017/1/74-L & L/Prod.]

S. M. Y. NADEEM, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जून, 1979

का०आ० 2430.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० जी०जी०एस०-VII से जी० जी० एस०-I तक पैट्रोलियम के लिये भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन कर लिया है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 10-4-78 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः, अब, पैट्रोलियम पाइपलाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

जी०जी०एस०-VII से जी०जी०एस०-I तक पाइपलाइन कार्य समाप्ती ।

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की	कार्य समाप्ति की तिथि
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	उवारसद सेरथा	600	17-2-79	10-4-78

[सं० 12016/16/79-प्रोड० 1]

New Delhi, 29th June, 1979

S.O.2430.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the Schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. GGS VII to GGS I in Kalol oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 10-4-78.

Now, therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963; the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from d.s.GGS VII to GGS I.

Name of Ministry	Village	S.O.No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Uvarsad Sertha	600	17-2-79	10-4-78

[No. 12016/16/79-Prod. I]

का० आ० 2431.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० झालोरा जी०जी०एस० से जी०जी०एस० एस०आई०पी० तक पैट्रोलियम के लिये भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन कर लिया है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 28-3-79 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पैट्रोलियम पाइपलाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

झालोरा जी० जी० एस० से जी० जी० एस० एस० आई० पी० तक पाइपलाइन कार्य समाप्ती ।

मंत्रालय का नाम	गांव	भा०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	मेरडा आदरज अमलीआरा वडावी हाजीपुर भीमासन	965	17-3-79	28-3-79

[सं० 12016/16/79-प्रो०-II]

S.O. 2431.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the Schedule appended thereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from GGS Jhalora to GGS Sipt in Kalol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 28-3-1979.

Now, therefor, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from GGS. Jhalora to GGS Sip.

Name of Ministry	Villages	S.O.No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Merda Adraj Amaliyara Vadavi Hajipur Bhimasan	965	17-3-1979	28-3-1979

[No. 12016/16/79-PRod.II]

शुद्धि-पत्र

का० आ० 2432.—भारत सरकार के राजपत्र-भाग-II खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 9 सितम्बर, 1978 के का० आ० संख्या 2605 के अन्तर्गत प्रकाशित भारत सरकार पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या 12016/6/78-प्रो०ड० दिनांक 11 अगस्त, 1978 के अधीन निम्नलिखित अनुसार के स्थान पर नीचे दी गई अनुसूची पढ़ें :—

पढ़ें				के लिए			
तालुका कलोल जिला मेहसान, गांव : सर्वे नं० : हेक्टेयर एआरई सेन्टीयर				तालुका : कलोल जिला-मेहसाना गांव सर्वे नं० हक्टेयर एआरई			
कलोल	593/2	0—10—20		कलोल	573/2	0—23—10	
	593/3	0—12—90		सईज	97	0—14—70	
सईज	97/4	0—02—55					
	97/5	0—08—70					
	97/6	0—04—00					

[सं० 12016/6/78 प्रो०ड०]

एस० एम० वाई० नदीम, अवर सचिव

ERRATUM

S.O. 2432.—In the notification of Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum) No.12016/6/78-PROD-I dated 11-8-1978 under S.O.No.2605 in the Gazette of Government of India, Part-II Section 3, Sub-Section (ii) dated 9th September, 1978.

READ					FOR				
Taluk : Kalol			District : Mehsana		Taluka : Kalol			District : Mehsana	
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare	Village	Survey No.	Hectare	Are	Centrare
Kalol	593/2	0	10	20	Kalol	593/2	0	23	10
	593/3	0	12	90					
Saij	97/4	0	02	55	Saij	97	0	14	70
	97/5	0	08	70					
	97/6	0	04	00					

[No. 12016/6/78-Prod.]

S. M. Y. NADEEM, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 जून, 1979

का० आ० 2433.—केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अशोक कुमार को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं० एफ 14-24/71-पी एच तारीख 6 अक्तूबर, 1971 द्वारा घोषित स्थानीय क्षेत्र के लिए खाद्य निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० पी 15014/6/78-पी एच (एफ एन) सी पी एफ ए]
जी० पंचपकेसन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 25th June, 1979

S.O. 2433.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri Ashok Kumar as Food Inspector for the local area declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) No. F. 14-24/71-PH, dated the 6th October, 1971.

[No. P. 15014/6/78-PH(F&N)PFA]
G. PANCHAPAKESAN, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 26 जून, 1979

का० आ० 2434.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने निर्मल टेलीफ़ोन केन्द्र में दिनांक 16-7-79 से प्रमाणित दर प्रणाली लाग करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-7/79 पी एच बी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

New Delhi, the 26th June, 1979

S.O. 2434.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16-7-1979 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Nirmal Telephone Exchange, Andhra Pradesh Circle.

[No. 5-7/79-PHB]

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1979

का. आ. 2435.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने त्रिवेलोर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-8-79 से प्रमाणित दरप्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-5/79-पी. एच. बी.]
आर. सी. कटारिया, सहायक महानिदेशक (पी. एच. बी.)

New Delhi, the 5th July, 1979

S.O. 2435.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 1-8-1979 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Trivellore Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-5/79-PHB]
R. C. KATARIA, Asstt. Director General (PHB)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 जून, 1979

का० आ० 2436.—कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खंड (घ) के अनुसरण में श्री सैयद बशीर अहमद के स्थान पर श्री टी० पी० इसर, आयुक्त और सचिव, कर्नाटक सरकार, समाज कल्याण और श्रम विभाग, बंगलौर, को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1517 दिनांक 14 अप्रैल, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 15 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"श्री टी० पी० इसर,
आयुक्त और सचिव, कर्नाटक सरकार,
समाज कल्याण और श्रम विभाग,
बंगलौर।"

[सं० यू-16012/3/76-एच० आई०]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 26th June, 1979

S.O. 2436.—Whereas the State Government of Karnataka has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri T. P. Issar, Commissioner and Secretary to the Government of Karnataka, Social Welfare and Labour Department, Bangalore, to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation in place of Shri Syed Basheer Ahmed;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1517, dated the 14th April, 1976, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)", for the entry against item 15, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri T. P. Issar,
Commissioner & Secretary to the
Govt. of Karnataka,
Social Welfare & Labour Deptt.,
Bangalore."

[No. U-16012/3/76-HI]

का० आ० 2437.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डेल्टा इण्टरप्राइजेज (प्राइवेट) लिमिटेड, 2ए, मोनालिसा, 17, कैमक स्ट्रीट, कलकत्ता-17, जिसके अन्तर्गत 3-बी कार्सटीन प्लेस, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एम-35017/26/79-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 2437.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Delta Enterprises (Private) Limited, 2A, Monalisa, 17, Camac Street, Calcutta-17 including its branch at 3-B Carstin Place, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of July, 1978.

[No. S. 35017/26/79-PF. II(i)]

का० आ० 2438.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 जुलाई, 1978 से मैसर्स डेल्टा इण्टरप्राइजेज (प्राइवेट) लिमिटेड, 2ए, मोनालिसा, 17, कैमक स्ट्रीट, कलकत्ता-17, जिसके अन्तर्गत 3-बी, कार्सटीन प्लेस, कलकत्ता-1, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एम-35017/26/79-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 2438.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty-first day of July, 1978 the establishment known as Messrs Delta Enterprises (Private) Limited, 2A, Monalisa, 17, Camac Street, Calcutta-17 including its branch at 3-B, Carstin Place, Calcutta-1, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017/26/79-PF.II(ii)]

का० आ० 2439.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि जॉन्स पैक, 9/6 उद्योग नगर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, एम० वी० रोड, गोरेगांव (पश्चिम), मुम्बई-62, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35018(62)/79-पी० एफ-2]

S.O. 2439.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs John's Pack, 9/6 Udyog Nagar Industrial Estate, S. V. Road, Goregaon (West) Bombay-62, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35018/62/79-PF.II]

का० आ० 2440.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजश्री कम्बाइन, शालीमार बिल्डिंग, 335, मौलाना शौकतअली रोड, ग्रांट रोड, मुम्बई-7, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एम० 35018(63)/79-पी० एफ-2(i)]

S.O. 2440.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajshri Combine, Shalimar Building, 335, Maulana Shaukatali Road, Grant Road, Bombay-7, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35018/63/79-PF.II(i)]

का० आ० 2441.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1976 से मैसर्स राजश्री कम्बाइन, शालीमार बिल्डिंग, 335, मौलाना शौकतअली रोड, ग्रांट रोड, मुम्बई-7, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35018(63)/79-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 2441.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1976 the establishment known as Messrs Rajshri Combine, Shalimar Building, 335, Maulana Shaukatali Road, Grant Road, Bombay-7, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/63/79-PF.II(ii)]

का० आ० 2442.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजश्री एक्जिबिटर्स, शालीमार बिल्डिंग, 335, मौलाना शौकतअली रोड, ग्रांट रोड, मुम्बई-7 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018/64/79-पी० एफ० II(i)]

S.O. 2442. Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajshri Exhibitors, Shalimar Building, 335, Maulana Shaukatali Road, Grant Road, Bombay-7, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1979.

[No. S. 35018/64/79-PF. II(i)]

का० आ० 2443.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1976 से मैसर्स राजश्री एक्जिबिटर्स, शालीमार बिल्डिंग, 335, मौलाना शौकतअली रोड, ग्रांट रोड, मुम्बई-7 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35018/64/79-पी० एफ० 2 (ii)]

S.O. 2443.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1976 the establishment known as M/s. Rajshri Exhibitors, Shalimar Building, 355, Maulana Shaukatali Road, Grant Road, Bombay-7, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/64/79-PF. II(ii)]

का० आ० 2444.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजश्री इण्टरप्राइजेज, शालीमार बिल्डिंग, 335, मौलाना शौकतअली रोड ग्रांट रोड, मुम्बई-7 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018/65/79-पी० एफ०-2(i)]

S.O. 2444.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajshri Enterprises, Shalimar Building, 335, Maulana Shaukatali Road, Grant Road, Bombay-7, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment ;

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35018/65/79-PF. II(i)]

का० आ० 2445.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1976 से मैसर्स राजश्री इण्टरप्राइजेज, शालीमार बिल्डिंग, 335, मौलाना शौकतअली रोड, ग्रांट रोड, मुम्बई-7 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35018(65)/79-पी० एफ०-2 (ii)]

S.O. 2445.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1976 the establishment known as Messrs. Rajshri Enterprises Shalimar Building, 335, Maulana Shaukatali Road, Grant Road, Bombay-7 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/65/79-PF. II(ii)]

का० आ० 2446.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजश्री फिल्म्स, शालीमार सिनेमा बिल्डिंग, 335, मौलाना शौकतअली रोड, मुम्बई-7 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018/66/79-पी० एफ०-II (ii)]

S.O. 2446.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajshri Films, Shalimar Cinema Building 335, Mauluna Shaukatali Road, Bombay-7, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment ;

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35018/66/79-PF. II(ii)]

का० आ० 2447.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1976 से मैसर्स राजश्री फिल्म्स शालीमार सिनेमा बिल्डिंग, 335, मौलाना शौकतअली रोड, ग्रांट रोड, मुम्बई-7 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35018/66/79-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 2447.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1976 the establishment known as Messrs Rajshri Films, Shalimar Cinema Building, 335, Maulana Shaukatali Road, Grant Road, Bombay-7 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/66/79-PF. II(ii)]

का० आ० 2448.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजश्री ऐसोसिएट्स शालीमार बिल्डिंग, 335, मौलाना शौकतअली रोड, ग्रांट रोड, मुम्बई-7, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस० 35018/67/79/-पी० एफ०-2 (i)]

S.O. 2448.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajshri Associates, Shalimar Building, 335, Maulana Shaukatali Road, Grant Road, Bombay-7, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment ;

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35018/67/79-PF. II(i)]

का० आ० 2449.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1976 से मैसर्स राजश्री एसोसिएट्स शालीमार बिल्डिंग 335, मौलाना शौकतअली रोड ग्रांट रोड मुम्बई-7 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस०-35018(67)/79-पी० एफ०-II(ii)]

S.O. 2449.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1976 the establishment known as Messrs Rajshri Associates, Shalimar Building, 335, Maulana Shaukatali Road, Grant Road, Bombay-7, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/67/79-PF. II(ii)]

का० आ० 2450.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बहार इण्टरप्राइजेज, शालीमार सिनेमा बिल्डिंग, 335, मौलाना शौकतअली रोड, ग्रांट रोड, मुम्बई-7, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018(68)/79-पी० एफ० 2 (i)]

S.O. 2450.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bahar Enterprises, Shalimar Cinema Building, 335, Maulana Shaukatali Road, Grant Road, Bombay-7, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35018/68/79-PF. II(i)]

का० आ० 2451.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1976 से मैसर्स बहार इण्टरप्राइजेज, शालीमार सिनेमा बिल्डिंग, 335, मौलाना शौकतअली रोड, ग्रांट रोड, मुम्बई-7, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस०-35018(68)/79-पी० एफ०-2 (ii)]

S.O. 2451.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1976 the establishment known as Messrs. Bahar Enterprises, Shalimar Cinema Building, 335, Maulana Shaukatali Road, Grant Road, Bombay-7, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/68/79-PF. II(ii)]

का० आ० 2452.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कादेर एक्सपोर्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 83, जेल रोड, (दक्षिण), मुम्बई-9 जिसके अन्तर्गत 31, फारुक एस०, उमेरभाई मार्ग, धाईकुला, मुम्बई-8 स्थित उसकी शाखा भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018(69)/79-पी० एफ०-2 (i)]

S.O. 2452.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kader Exports

(Private) Limited, 83, Jail Road, (South), Bombay-9 including its branch at 31, Faruk S. Umerbhai Marg, Byculla, Bombay-8, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, he Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1978.

[No. S. 35018/69/79-PF. II(i)]

का० आ० 2453—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जुलाई, 1978 से मैसर्स कादेर एक्सपोर्टस् (प्राइवेट) लिमिटेड, 83, जेल रोड, (दक्षिण), मुम्बई-9, जिसके अंतर्गत 31, फारूक एस० उमेरभाई मार्ग, बाईकुला, मुम्बई-8 स्थित उसकी शाखा भी है, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एम०-35018(69)/79-पी० एफ०-2(ii)]

S.O. 2453.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter hereby specifies with effect from the first day of July, 1978 the establishment known as Messrs. Kader Exports (Private) Limited, 83, Jail Road, (South), Bombay-9 including its branch at 31, Faruk S. Umerbhai Marg, Byculla, Bombay-8, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/69/79-PF. II(ii)]

का. आ. 2454.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वीनर्स एंड लामिनेशन्स (इण्डिया) लिमिटेड, एस. जी. रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-2 जिसके अंतर्गत पश्चिम ओथारा, तिरुवल्ला, स्थित उसका कारखाना भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस.-35019(75)/79-पी. एफ.-2]

S.O. 2454.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Veeners and Laminations (India) Limited, M. G. Road, Ernakulam, Cochin-11 including its Factory at West Othara, Tiruvalla, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1978.

[No. S. 35019/75/79-PF-II]

का० आ० 2455—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स महालक्ष्मी स्पन पाइप्स कम्पनी, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, एच० एम० टी० पो० आ० हैदराबाद-54 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है, कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(80)/79-पी० एफ० II(i)]

S.O. 2455.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mahalaxmi Spun Pipes Company, Industrial Development Area, H.M.T. Post Office, Hyderabad-54, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1976.

[No. S. 35019/80/79-PF. II(i)]

का० आ० 2456—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 मई, 1976 से मैसर्स महालक्ष्मी स्पन पाइप्स कम्पनी, इन्डस्ट्रियल डेवलेपमेन्ट एरिया एच० एम० टी० पो० आ० हैदराबाद-54, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एम०-35019/80/79-पी० एफ० II (ii)]

S.O. 2456.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of May, 1976 the establishment known as Messrs Mahalaxmi Spun Pipes Company, Industrial Development Area, H.M.T. Post Office, Hyderabad-54, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/80/79-PF. II(ii)]

का० आ० 2457—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फतुवा फुलवारी शरीफ ग्राम्य विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड, रोड नं० 2-बी, राजेन्द्र नगर, पटना-16 जिसके अंतर्गत (1) डाकघर कंकड़बाग कालोनी, पटना और (2) डाकघर फतुवा, स्थित उसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(82)/79-पी० एफ०-II]

S.O. 2457.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Fatwah Phulwarishariff Gramya Vidyut Sahakari Samiti Limited, Road, No. 2B, Rajendra Nagar, Patna-16 including its branches at (1) Post Office Kanarbagh Colony, Patna and (2) Post Office Futwah, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1978.

[No. S. 35019/82/79-PF. II]

का० आ० 2458.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स खेतान ऑटोट्रैक्ट (प्राइवेट) लिमिटेड एक्जीबिशन रोड पटना-1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/83/79-पी० एफ०-II]

S.O. 2458.—Whereas it appears to the Central Government that the employed and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Khetan Autotract (Private) Limited, Exhibition Road, Patna-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1979.

[No. S. 35019/83/79-PF. II]

का० आ० 2459.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आरगानिक इण्टरमिडिएट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 58, सेक्टर ए, इण्डस्ट्रियल एरिया, सावेर रोड, इंदौर-3 (मध्य प्रदेश), नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस 35019 (85)/79-पी० एफ०-2(i)]

S.O. 2459.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Organic Intermediates (Private) Limited, 58, Sector A, Industrial Area, Sanwer Road, Indore-3 (Madhya Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1978.

[No. S. 35019/85/79-PF. II (i)]

का० आ० 2460.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 सितम्बर, 1978 से मैसर्स आरगानिक इण्टरमिडिएट्स (प्राइवेट) लिमिटेड 58, सेक्टर ए, इण्डस्ट्रियल एरिया सावेर रोड, इन्दौर-3 (मध्यप्रदेश) नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35019 (85)/79-पी० एफ०-2(ii)]

S.O. 2460.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of September, 1978 the establishment known as Messrs. Organic Intermediates (Private) Limited, 58, Sector A, Industrial Area, Sanwer Road, Indore-3 (Madhya Pradesh), for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/85/79-PF. II (ii)]

नई दिल्ली, 30 जून, 1979

का० आ० 2461.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डेकोहोम, 28बी, शेक्सपीयर सारणी, कलकत्ता-17 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35017(25)/79-पी एफ-2]

New Delhi, the 30 h June, 1979

S.O. 2461.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Decohome, 28 B, Shakespoar Sarani, Calcutta-17, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1977.

[No. S. 35017/25/79-PF II]

का० आ० 2462.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बिहार कंसट्रक्शन कम्पनी, ई 158ए ब्लाक, सोनारी जमशेदपुर-II, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(79)79-पी एफ० II(1)]

S.O. 2462.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bihar Construction Company, E/158 A Block, Sonari, Jamshedpur-11, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central

Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1979.

[No. S. 35019 (79)/79-PF. II (i)]

का० आ० 2463.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 मार्च, 1979 से मैसर्स बिहार कंसट्रक्शन कम्पनी, ई/ 158 ए ब्लाक, सोनारी, जमशेदपुर-11 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35019(79)/79-पी० एफ० II(II)]

हंस राज छाबड़ा उप सचिव

S.O. 2463.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of March, 1979 the establishment known as Messrs Bihar Construction Company, E/158 A Block, Sonari, Jamshedpur-11, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(79)/79-PF. II(ii)]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

New Delhi, the 28th June, 1979

S.O. 2464.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th June, 1979.

BEFORE SHRI S. N. JOHRI, B. SC., LL.M. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M. P.)

Case No. CGIT/LC(R)(3)/1979

PARTIES :

Employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen represented through the Secretary, Food Corporation of India Employees Union, Chunna Bhatti Road, Ajni, C/o F. C. I. Nagpur-440015.

APPEARANCES :

For Union S/Shri L. S. Ahuja & N. S. Shukla.

For Management S/Shri M. B. Surodaya & R. M. Gomashe, Asstt. Manager (Quality Control).

INDUSTRY : Food Corporation DISTRICT : Nagpur (M.S.)

Dated 14th June, 1979

AWARD

This is a reference made by the Govt. of India in the Ministry of Labour vide its Order No. L-42011(18)/78-D-II(B), dated 28th February, 1979, for the adjudication of the following industrial dispute :

"Whether the action of the management of the Food Corporation of India in refusing the payment of wages for weekly off days to the casual workers employed at the District Manager's Unit of the Food Corporation of India, Nagpur, is justified ? If not to what relief are the workmen entitled and from what date ?"

2. It is not disputed that the contract system in the Food Corporation of India in Nagpur was discontinued from 23rd March, 1974 and since that time the contractor's labourers were directly engaged by the management as casual labourers. They are covered by Employees Provident Fund Scheme, Gratuity Act, Bonus Act and Workmen's Compensation Act. They are paid overtime allowance whenever they are required to do overtime work. They are also paid for the three national holidays of 26th January, 15th August and 2nd October even when no work is taken from them on those days. However, they are not paid for the weekly rest since the time they have been taken directly on the rolls of the management even when prior to that when they were engaged by the contractors a clause under the contract made by the contractor with the management stipulated that he shall be liable to give paid weekly rest to the workers after six days' continuous work, as if the workmen had been on duty on the weekly rest day as well. There are no Certified Standing Orders of the Corporation and therefore the Model Standing Orders apply.

3. The case of the Union is that a demand to that effect with respect to the employees of District Nagpur Unit of Food Corporation of India was raised but the management did not concede to it.

4. The case of the management is that the employment on handling of foodgrains at the depots is not a scheduled employment under Minimum Wages Act and as such paid weekly off cannot be insisted upon by the casual labourers there being no law to give such payment. A demand of that type could not be conceded. A permanent employee continues to be an employee of the Corporation till his services are terminated by the recognised modes of employment while in the case of casual labourers there is no such continuity of employment beyond the actual hours of work for a particular day. Therefore it is alleged that the question of giving paid weekly off to casual labourers has no rational basis. The casual labourers are employed on no work no pay basis, and there is no jural-tie existing between the Corporation and the casual labourers after working hours. The contractor was bound in the agreement to pay the contract labourers for the weekly off because the labourers under the contractor continued to be the employees of the contactor beyond the actual hours of work on a particular day and as such were entitled to paid weekly off. The situation has changed since the management has taken over the employment directly.

5. Contract labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 was enacted for the benefit of the labourers and not for the benefit of the indirect employers (principal employers). It is a paradox that a Government Corporation employer which was insisting upon the contractor to pay weekly off to the contractor's labourers for one days rest after six days continuous work, has after abolition of contract shown the magnanimity of absorbing the contractor's labourers and yet has meticulously avoided to follow its own rule imposed upon the contractor of giving paid-weekly rest though neither the nature of duties nor the nature of work, nor the nature of employment has changed except that the contractor has been replaced by the principal employer. This not only sounds unresasonable but unjust as well.

6. A plea has been taken by the management that the contractor's labourers were in the continuous employment of the contractor and therefore with the continued relationship the contractor was duty bound to pay for the weekly off while there is no such continuity of employment of these casual labourers with the Food Corporation of India and therefore no such payment can be envisaged. This alleged distinguishing feature is devoid of substance. Contract from laying down the terms and conditions of the contract is Ex. W|3. It nowhere contemplates that all the contractor's labourers shall be the permanent employees of the contractor. It was not possible for the contractor to give permanent employment to the labourers nor was it possible for him to give even temporary employment on monthly basis. Clause (b) at page 4 of the contract form gives the brief description of work. That was to be undertaken by the contractor. It is 'unloading/loading of foodgrain bags from into railway wagons, trucks etc., stacking the foodgrain bags, bagging, rebagging, weighment, standardisation, cleaning of foodgrains etc., and transporting of foodgrains from railway station to Corporation godowns or vice versa or transporting them from any place to any other place'. Clause (c) on the same page states with respect to he volume of work that

no definite volume of work to be performed could be guaranteed during the currency of contract. Thus the work continues to be as fluctuating as it was when the contract used to be given. If due to that fluctuating nature of the work the management is unable to assess a minimum number of the workmen which can be permanently employed, it could hardly be possible for the contractor to employ labourers on a continued employment basis. There is no evidence that he was a general contractor catering the manpower need of several other industries so that he could employ some labourers on permanent or quasi-permanent basis in the hope of providing them elsewhere if not in Food Corporation of India. It is thus obvious that the contractor was also employing the labourers on day to day basis. There is no evidence to the contrary. Under the circumstances, it is preposterous to distinguish the present employment from the previous one by saying that there was continuity of service with the contractor hence paid weekly off was enforced against him, while there is no continuity of employment with the present management hence that benefit cannot be granted. The distinction so drawn is a meaningless effort to distort facts when no evidence has been produced before me to show that the contractor used to engage the labourers on continuity of employment basis and paid them even when he had no work for them.

7. The terms of the contract with the contractor as they used to be and as they are reflected in the form Ex. W|3 go to show a great anxiety on the part of the employer, Food Corporation of India, to see that all welfare and health responsibilities are fully discharged by the contractor in respect of canteens, rest rooms, latrines, urinals, washing facilities, first aid facilities etc. and of security provided to the labourers with respect to wages, paid weekly off, attendance allowance and all liability is discharged by him under Workmen Compensation Act, Factories Act etc. Strangely enough when it came under the direct relationship of these casual workers, the same institution which was so anxious to look to the interest of labourers at that time, is resorting to legal technicalities, and trying to find odd distinctions for circumventing the same condition of giving paid weekly off to the same workers as if the abolition of the contract was contemplated to work against the interest of the workers.

8. The provision for the payment of wages for the weekly off as incorporated on page 12 of the contract form Ex. W/3 runs as follows :—

> "The contractors shall allow or cause to be allowed to the workers directly or indirectly employed in the work one day's rest for six days' continuous work and pay wages at the same rate as on duty".

The caluse thus envisages payment of wages for the weekly off in case of continuous work for six days by a workman irrespective of the fact whether there is continuity of employment for a further period or not. Whatever be the nature of employment the six days continuous working by implication means the earning of the wages for the 7th day's off. The provision nowhere contemplates that such a workman should be engaged on temporary or permanent basis or that it should be paid to only those workers whose employment is not on day to day basis. At present also the charts show the datewise engagement of the casual labourers (Ex. W/2) and that a sufficiently good number of casual labourers are required to be engaged every day by the Corporation and the number is on the increase This gives sufficient indication of the fact that the work is of permanent nature and the engagement is also a continuous one except for certain breaks or exceptionally when there is no work requiring engagement of so many casual labourers. These casual labourers therefore may be technically in employment on day to day basis but factually they work for continuous periods with an implied assurance that except for intermittent periods when there is less work to warrant employment of all, their re-employment or continuity of employment is almost assured. For example, Sri Ravindra Shinde (W.W. 1) has stated on oath that he had been working in the Food Corporation of India as casual labourers for the last nine years. Prior to 1974 he was an employee of the contractor and since 1974 is working with the Food Corporation of India directly. This long spell of working of the worker generally is further indicative of the fact that neither the nature of the work is so casual nor the employment is so fragile. Shri N. S. Shukla, Secretary of the Union, has sent a copy of the letter (No. MSW|NGP|CSD|GI-N/79, dated 2nd May, 1979) from Maharashtra State Ware Housing Corporation attested by the District Manager, Food Corporation of India at Nagpur. The letter mentioned that the casual labourers engaged by Maharashtra State Ware Housing Corporation are given paid weekly off.

9. I am, therefore, of the view that on principles of social justice and in the light of the historical facts of imposition of the conditions of paid weekly off to the contract labourers by the contractor and with a view to see that the contract abolition, which was mean to protect the interest of the labourers, should not be so applied as to work against their interest, as well as considering the system of such payment prevailing in sister concern at Nagpur, on industry-cum-region basis, it is held at not justified on the part of the management to refuse paid weekly off to such of the casual labourers who have continuously worked for six days in that week. The award shall be effective from the date of reference, i.e., 28th February, 1979. Management should make payments accordingly. It shall further pay Rs. 100 as costs of this litigation to the Union.

N. S. JOHRI, Presiding Officer
[No. L-42011(18)/78-D.II(B)]
HARBANS BAHADUR, Desk Officer.

नई दिल्ली, 11 जून, 1979

का० आ० 2465—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में भारतीय स्टेट बैंक, गूडूर, नैल्लूर जिला के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एस० सदाशिव रेड्डी होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती

अनुसूची

"या भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद सर्किल के प्रबन्धतंत्र के लिए श्री सी० एल० वी० प्रसाद, क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, भारतीय स्टेट बैंक गूडूर ब्राच, नैल्लूर जिला को, दो वर्ष के लिए वेतन-वृद्धि रोककर दंड देना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल० 12012/95/78-डी० 2(ए)]
एम० के० मुखर्जी, अवर सचिव

New Delhi, the 11th June, 1979

S.O. 2465.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of State Bank of India, Gudur, Nellore Distt. and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri S. Sadasiva Reddy shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the management of State Bank of India, Hyderabad Circle is justified in punishing Shri C.L.V. Prasad, Clerk-cum-Typist, State Bank of India, Gudur Branch, Nellore Distt. with stoppage of increment for two years ? If not, to what relief the said workman is entitled ?"

[No. L-12012/95/78-D. II. A]
S. K. MUKERJEE, Under Secy.

New Delhi, the 30th June, 1979

S.O. 2466.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Nudkhurkee Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nudkhurkee, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th June, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3 DHANBAD

Reference No. 36 of 1977

PARTIES :

Employer in relation to the management of Nudkhurjee Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O Nudkhurkee, Distt. Dhanbad.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For Employers.—Shri K. P. Rewani, Representative of the management.

For Workmen.—Workmen in person.

INDUSTRY : Coal STATE : Bihar.

Dated, the 21st June, 1979

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them u/s. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 14 of 1947 have referred the following dispute to this Tribunal for adjudication as per their Order No. L-20012/70/75-III-A, dated 22nd September, 1975.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Nudkhurkee Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited P.O. Nudkhurkee, Distt. Dhanbad, in dismissing Sarvashri Bu'an Saw, Chaprasi, Prahlad Dusad, Miner and Harinath Ram, Miner, from service with effect from the 25th December, 1974 is justified ? If not, to what relief are the said workmen entitled ?"

The Koyla Mazdoor Union on behalf of the workmen herein has filed a statement of claim stating that the workmen Sri Bhutan Saw, Chaprasi, Sri Harinath Ram, Miner and Sri Baban Rewani, Miner (Rewani is not a concerned workman in this dispute) were served with a chargesheet dated 25-3-74 for the alleged offence of assaulting Sri R. K. Jain, Manager, Nudkhurjee Colliery. The other workman concerned herein viz. Prahalad Dusad, Miner and another Sheodani Saw, Miner were served with another chargesheet dated 14-4-74 in respect of the same offence. The management appointed Sri N. L. Singh as an Enquiry Officer. The workmen submit that the said Enquiry Officer was not appointed by a competent authority. They also say that as the Enquiry Officer was a member of the Executive Committee of the Coal Mines Officers' Association he had bias in favour of the officer Sri R. K. Jain the alleged victim of the assault. They also complain that because of bias the Enquiry Officer did not permit Ram Ayodhya Singh a co-worker of the delinquent employees to conduct their defence. They also stated that the Inquiry Officer started recording proceedings in a language not intelligible to the workmen. The workmen protested against this. It is also complained that the Enquiry Officer was guilty of tempering with the evidence that was already recorded by him. They urged several other reasons questioning the validity of the enquiry. The workmen prayed that this Tribunal may be pleased to order their reinstatement with full back wages and continuity of service after setting aside the Enquiry Officer's findings.

The management filed a written statement stating that the enquiry was fair and proper and the findings of the Enquiry Officer were based on proper evidence. They say that Ram Ayodhya was not allowed to represent the workmen before the Enquiry Officer for the reason that he was not a co-worker of theirs. The said Ram Ayodhya Singh was an employee of Benedih Colliery a different organisation. Thereafter the workmen were allowed to be represented by Sri B. Mukherjee an Overman at their request. They say that the enquiry proceedings were conducted in Hindi and signed by the concerned workmen and their representative and the others present. The General Manager accepted the findings of guilty recorded by the Enquiry Officer and having regard to the seriousness of the offence awarded the punishment of dismissal with effect from 25-12-74. It is submitted that there are no grounds for interference with the order of dismissal passed by the management.

Mr. S. R. Sinha, my learned predecessor by his order dated 7-1-78 held that the enquiry was not vitiated by any flaw or non-observance of the principles of natural justice. He also held that the conclusion arrived at by the Enquiry Officer was correct on the evidence. For further hearing the case has undergone several adjournments till 21-6-79.

On 21-6-79 the three workmen herein and Sri K. P. Rewani an assistant in the personnel Department appearing in person filed a memo of settlement requesting the Court to pass an award in terms thereof. The parties admitted the terms of compromise. In the circumstances of the present case the compromise is considered to be fair and in the interests of the workmen and therefore recorded.

This reference is therefore answered in terms of the memo of settlement, a copy of which is appended hereto. The said memo of settlement may be read as part of this award.

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

MEMORANDUM OF SETTLEMENT UNDER RULE 58(4) OF THE INDCSTRIAL DISPUTES (C) RULES, 1957

BETWEEN KOYALA MAZDOOR UNION AND BHARAT COKING COAL LIMITED : BARORA AREA

Representing Management	Representing Workmen
Sri H. N. Tripathy, G. M., Barora Area.	Sri Ram Ayodhya Singh, Secretary, Koyala Mazdoor Union, Nudkhurkee Colliery.

SHORT RECITAL

Sri Butan Shaw, Chaprasi, Hari Nath Ram, Miner and Prahlad Dusadh, Miner of Nudkhurkee Colliery had been dismissed and the consequent industrial dispute was referred for adjudication and registered as reference No. 115/75 (old), 36/77 (New), which has been pending proceeding. Since the disposal of the case is delayed because of vacancy in the Tribunal. The workmen/Union approached the management for a compromise settlement and the matter was taken up for negotiation. As a result the party have now arrived at a settlement and the terms stated below.

Terms of Settlement

(1) The parties agree that Harinath Ram and Prahlad Dusadh will be reinstated in their original posts in any colliery of Barora Area within 15 days of their reporting for duty to the General Manager, Barora Area.

(2) The parties agree that Sri Butan Shaw, Chaprasi who was transferred earlier to Gobindpur colliery before dismissal will be reinstated in his original post within 15 days and his place of posting will be decided by D.I.C./Chief Security, BCCL.

(3) The parties agree that if the workmen fail to report for duty within 15 days of the date of settlement their claim for reinstatement will stand forfeited.

(4) The parties agree that the continuity of service of the abovenamed workmen shall be mentioned by the management for the purpose of retrenchment and gratuity only.

(5) The parties agree that the concerned workmen/Union shall not claim any payment of wages in any form, bonus, and increment etc. for the period of the idleness, from their date of dismissal to date of resumation of duty.

(6) The parties agree that the settlement fully and finally resolves all disputes relating to their dismissal, and that they shall have no further claim against other in this respect.

(7) The parties agree that they shall file a joint compromise petition before the tribunal for settlement of the reference No. 36/77

(8) The parties agree that the copies of the settlement shall be forwarded to the authorities under the rules for registration.

Signature

Signature

(H. N. Tripathy)
General Manager.
Barora Area.
Dated 21-6-79

(Ram Ayodhaya Singh)
Secretary, K. M. U.
Dated 21-6-79

WITNESSES

1. Sri Butan Shaw
2. Sri Harinath Ram
3. Sri Prahlad Dusadh

Dated :

[No. L-20012/70/75-D. III(A)]

S.O. 2467.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Shampur 'A' Colliery of Eastern Coalfields Ltd., Post Office Nirsachatti, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th June, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3

DHANBAD

Reference No. 85 of 1977

PARTIES :

Employers in relation to the management of Shampur 'A' Colliery of Eastern Coalfields Ltd., P. O. Nirsachatti, Dist. Dhanbad.

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

For Employers.—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

For Workman.—Shri S. Bose, Secretary of the union.

Industry : Coal State : Bihar

Dated, the 21st June, 1979

AWARD

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them u/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947) have referred the following dispute to this Tribunal for adjudication as per their Order No. L-20012/107/77-DIII(A), dated 26th November, 1977.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Shampur 'A' Colliery of Eastern Coalfields Ltd., P. O. Nirsachatti, Dist. Dhanbad in dismissing Shri Bhola Nath Mondal, Mining Sirdar, with effect from 29th March, 1976 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

The Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh filed a statement of claim on behalf of the workman herein stating that during the relevant period the workman herein was working as a Mining Sirdar in Selected Laikdih Section of Shampur 'A' Colliery. The Manager of the mine by his letter dated 28-8-75 alleged that he was guilty of miconduct in having permitted unauthorised persons to work in the Quarry either with or without the connivance of the other members of the staff. The workman submitted his explanation dated 30-8-75 denying the allegations made against him.

On 3-9-75 one Sri I. B. Pandey served a notice on the workman herein stating that he proposed to conduct an enquiry into the charges detailed in the chargesheet dated 28-8-75.

The workman stated that there was only a show of enquiry. Thereafter he received an order dated 29-3-76 dismissing him from service with immediate effect. The Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh took up the cause of the workman and approached the General Manager for reconsideration of their decision. Not having received any reply to that representation the matter was referred to A.L.C. (C) Dhanbad for conciliation. The management took an adament attitude towards the workman during conciliation proceedings. On receipt of the failure of conciliation report the Government have made the present reference. The workman submits that he had nothing to do with the recruitment or deployment of personnel in the Quarry and therefore he could not be proceeded against for some unauthorised persons being allowed to work in the mine. He prays that the order of dismissal may be set aside and he may be reinstated in service with full back wages.

The management in their written statement stated that in the month of August, 1975 the Supdt. of mines and the Senior Personnel Officer during the course of their check found the Form B Register to have been tampered with. The said 'B' Register was being maintained by the Attendance Clerk. Several inter-polations were found in the register. Father's/husband's names and addresses were found corrected. Even the names of some workmen in some cases were freshly added after erasing the previous entries. All the persons whose names and addresses had been found tampered with in that 'B' register were found working in the mine, where the workman herein was working as a Mining Sirdar. Therefore a chargesheet was issued to the workman herein, the Attendance Clerk and the Provident Fund Clerk. It is submitted that the enquiry was fairly and properly conducted in accordance with the provisions of law and the principles of natural justice. They submit that there is no cause for interference with the findings arrived at by the Enquiry Officer or in regard to the punishment imposed by the management on the workman herein.

The parties have filed their respective rejoinders.

On 17-4-78 a compromise was entered into between Shri K. S. Chatterjee, M.L.A. Bihar Colliery Kamgar Union representing the workman and the General Manager and Dy. personnel Manager on behalf of the management, whereby amongst other things the management agreed to reinstate the workman herein also with the other two employees dismissed for the offence in question without back wages. Shri S. Bose, Secretary of the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh appearing for the workman and Shri T. P. Choudhury appearing for the management requested the Court to pass an award in terms of the settlement. The settlement is recorded as it is felt that the same is in the interests of the workman herein.

In the result this reference is answered in terms of the memo of settlement filed by the parties. The said memo of settlement which is appended hereto may be read as part of this award.

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

Memorandum of Settlement between the Management of Shampur 'A' Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd. and their workmen, represented by the Bihar Colliery Kamgar Union, made this the 17th day of April, 1978

PRESENT

On behalf of the management

1. Shri N. C. Dash, General Manager.
2.
3. Shri M. P. Singh, Dy. P. M

On behalf of the workmen.

1. Shri K. S. Chatterjee, M.L.A. and Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.
2.
3.

Preamble

S/Shri B. C. Sahani, Provident Fund Clerk, K. C. Dutta, Attendance Clerk, Bhola Nath Mondal, Mining Sardar, were dismissed for misconduct for alleged tampering of Form 'B' Register, helping impersonation of workmen, showing negligence of duty etc. after a domestic enquiry following a charge-sheet dated 28-8-75. Industrial disputes were raised on their behalf, which are pending before the Central Government Industrial Tribunal No. 3 at Dhanbad, and which are numbered as Reference No. 72 of 1977, 73 of 1977 and 85 of 1977 respectively and are pending for adjudication.

All the concerned workmen have appealed to the Chairman-cum-Managing Director for their reinstatement.

Their cases were duly considered by the management on the background that at least two officers of the colliery were involved in this affair and in fact, they were aware of this impersonation. One of the officers was also proceeded against.

There was free and frank discussion between the management and Shri K. S. Chatterjee of the Bihar Colliery Kamgar Union, who sponsored the cases of the workmen before the Chairman-cum-Managing Director. In the background of very good industrial relations with the Bihar Colliery Kamgar Union, particularly after Sri K. S. Chatterjee has taken over the stewardship, the Chairman-cum-Managing Director has been pleased to agree on principle to the reinstatement of all the three concerned workmen, as stated above, to maintain Industrial Relations although the misconduct against them had been fully established and was indeed serious.

It is therefore, agreed as follows :—

(1) That S/Sri B. C. Sahani, Provident Fund Clerk, K. C. Dutta, Attendance Clerk and Bhola Nath Mondal, Mining Sardar of Shampur 'A' Colliery are hereby reinstated in their services with immediate effect but they will not get any back wages from the date of their dismissal till the date of joining their posts.

(2) That the entire period of their absence will be treated as leave without pay but their continuity of services will not be broken for the purpose of gratuity and/or other benefits.

(3) That the concerned workmen undertake not be indulge in such type of misconduct in future and assure the management of their full loyal co-operation.

(4) It is agreed that copy of this settlement shall be forwarded to the A.L.C. (Central) (Conciliation Officer), Dhanbad as required under Rule 58 (4) of the Industrial Disputes Act.

(5) It is further agreed that required number of copies of this settlement shall be filed before the Central Government Industrial Tribunal No. 3 at Dhanbad in each of the three References pending there with the prayer that the Tribunal will give his award in terms of this settlement.

For and on behalf of the Management

Sig. (Illegible)
Sig. (Illegible)

For and on behalf of the workmen.

B. C. Sahani
B. N. Mondal
K. C. Dutt

Witness :

Sig. (Illegible)
Sig. (Illegible)

1.
2.

[No. L-20012/107/77-D. III(A)]
S. H. S. IYER, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 15 जून, 1979

का० आ० 2468.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद, श्री एफ० एल० एफ० अलवारेस, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के समक्ष लंबित हैं ;

और श्री एफ० एल० एफ० अलवारेस की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33 ख की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० शनमुखप्पा होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त श्री एफ० एल० एफ० अलवारेस, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के समक्ष लंबित उक्त विवाद से संबद्ध कार्यवाही को वापस लेती है और उसे श्री एच० शनमुखप्पा, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण बंगलौर को इस निदेश के साथ अंतरित करती है कि उक्त अधिकरण उक्त कार्यवाही में उस प्रक्रम से कार्य प्रारम्भ करेगा, जिस पर वह उसे अंतरित की गई है तथा विधि के अनुसार उसका निपटान करेगा ।

अनुसूची

क्रमांक	विवाद के पक्षकार	निर्देश संख्या और तारीख
1	2	3
1.	मैसर्स तुन्गभद्रा मिनरल्स (प्रा०) लि०, तरानगर डाकखाना, सन्दूर तालुका, बेल्लरी जिला के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	सं० एल-29011/40/73-एल० आर० 4, दिनांक 29-9-73 [संदर्भ संख्या 4/73 (केन्द्रीय)] ।
2.	मैसर्स डालमिया इंटरनेशनल, हास्पेट के बी० आर० एच० आयरन और नमाइन्स के रेंजिंग कन्ट्रैक्टर, श्री आर० मुनीस्वामी के प्रबन्धतंत्र और उनके कर्मकार के बीच ।	सं० एल-26012/6/73-एल० आर० -4(ii), दिनांक 14-1-1974 [संदर्भ संख्या 1/74 (केन्द्रीय)] ।
3.	मैसर्स डालमिया इंटरनेशनल, हास्पेट के बी० आर० एच० आयरन और माइन्स के रेंजिंग कन्ट्रैक्टर, श्री एम० रमन के प्रबन्धतंत्र और उनके कर्मकारों के बीच ।	सं० एल०-25012/6/73- बी० आर०-4(i), दिनांक 14-1-1974 संदर्भ संख्या 2/74 (केन्द्रीय) ।
4.	भारतीय रिजर्व बैंक के नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच ।	सं० एल-12025/20/72-एल० आर०-3, दिनांक 10-1-1974 [संदर्भ संख्या 3/74 (केन्द्रीय)] ।
5.	मैसर्स डालमिया इंटरनेशनल हास्पेट, बेल्लेरी जिला के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	सं० एल०-29012/5/74- एल० आर०-4, दिनांक 23-1-1974 [संदर्भ संख्या 4/74 (केन्द्रीय)] ।
6.	मैसर्स डालमिया इंटरनेशनल, हास्पेट, बेल्लेरी जिला के कर्मकार और प्रबंधतंत्र ।	सं० एल०-26012/8/74-एल० आर०-4, दिनांक 21-10-1974 [संदर्भ संख्या 5/74 (केन्द्रीय)] ।
7.	मैसर्स डालमिया इंटरनेशनल, हास्पेट, बेल्लरी जिला के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	सं० एल-26011/12/74-एल० आर०-4, दिनांक 25-10-1974 [संदर्भ संख्या 6/74 (केन्द्रीय)] ।
8.	मैसर्स डालमिया इंटरनेशनल, हास्पेट, बैल्लेरी जिला के कर्मकार और प्रबंधतंत्र ।	सं० एल-26012/4/74-एल० आर० 4, दिनांक 15-11-1974 [संदर्भ संख्या 7/74 (केन्द्रीय)] ।
9.	मैसर्स डालमिया इंटरनेशनल, हास्पेट, बैल्लेरी जिला के बी० आर० एच० आयरन और माइन्स के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	सं० एल०-26011/8/74-एल० आर०-4, दिनांक 21-12-74 [संदर्भ संख्या 1/75 (केन्द्रीय)] ।

1	2	3
10.	मैसर्स डालमिया इंटरनेशनल हास्पेट, बेल्लेरी जिला के बी० आर० एच० आयरन और माइन्स के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र।	संख्या एल०-26012/6/74-एल० आर०-4 दिनांक 10-1-75 [संदर्भ संख्या 2/75 (केन्द्रीय)]।
11.	मैसर्स डालमिया इंटरनेशनल हास्पेट, के बी० आर० एच० आयरन और माइन्स के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र।	संख्या एल०-26011/13/74-एल० आर० 4 डी० 2-बी० दिनांक 27-1-75 [(संदर्भ संख्या 3/75 (केन्द्रीय)]।
12.	भारत गोल्ड माइन्स लि० ओरगम के० जी० एफ० के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र।	संख्या एल०-29012/9/74-एल० आर० 4 (डी० ओ० 3 बी० दिनांक 26-2-75 संदर्भ संख्या 4/75 (केन्द्रीय)।
13.	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, ओरगम, के० जी० एफ० के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र।	संख्या एल०-29012/25/74-एल० आर० 4 दिनांक 3-3-75 [(संदर्भ संख्या 5/75 (केन्द्रीय)]।
14.	मैसर्स डालमिया इंटरनेशनल हास्पेट, के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र।	संख्या एल०-26012/9/75डी० 4 बी' दिनांक 13-8-75 [संदर्भ संख्या 8/75 (केन्द्रीय)]।
15.	मैसर्स डालमिया इंटरनेशनल हास्पेट के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।	संख्या एल०-26012/10/75-डी० 4 (बी) दिनांक 26/8/75 [(संदर्भ संख्या 9/75 (केन्द्रीय)]।
16.	सिन्डीकेट बैंक मणीपाल के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र।	संख्या एल०-12012/18/73/एल० आर० 3 दिनांक सितम्बर 75 [संदर्भ संख्या 10/75 (केन्द्रीय)]।
17.	मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि० माइन्स डिवीजन नौमुन्डी की दोड्डाकन्या मेगनेसाइट माइन के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।	संख्या एल०-29011/3/76/डी० 3 (बी) दिनांक 17/3/86) [संदर्भ संख्या 2/76 (केन्द्रीय)]।
18.	विजय बैंक लिमिटेड बंगलौर के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।	संख्या एल०-12012/85/76-डी० 2 (ए) दिनांक 19-8-76 [संदर्भ संख्या 6/76 (केन्द्रीय)]।
19.	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के० जी० एफ० के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।	संख्या एल०-43012/6/76-डी० 4 (बी) दिनांक 3-9-76 [संदर्भ संख्या 7/76 (केन्द्रीय)]।
20.	भारतीय जीवन बीमा निगम बंगलौर के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।	संख्या एल०-17011/(7)/76-डी० 4 (ए) दिनांक 18-10-76 [संदर्भ संख्या 9/76 (केन्द्रीय)]।
21.	नेशनल इंशोरेंस कं० लि० बंगलौर के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।	संख्या एल०-17012(3)/75-डी० 2 (ए) दिनांक 5-7-76 [संदर्भ संख्या 1977 का 3 केन्द्रीय]।
22.	कर्नाटक बैंक लिमिटेड बंगलौर के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।	संख्या एल०-12012/2/78-डी० 2 (ए) दिनांक 28-3-78 [संदर्भ संख्या 1/78 (केन्द्रीय)]।
23.	मैसर्स भारत गोल्ड माइन्स रामगिरी की रामगिरी गोल्ड माइन्स प्रोजेक्ट के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।	संख्या एल०-4301/12/78-डी० 3 (बी) दिनांक 4-7-78 [संदर्भ संख्या 4/78 (केन्द्रीय)]।
24.	कर्नाटक बैंक लिमिटेड, बंगलौर के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।	संख्या एल०-12011/6/78-डी० 2 (ए) दिनांक 23-8-78 [संदर्भ संख्या 5/78 (केन्द्रीय)]।
25.	कर्नाटक बैंक लिमिटेड मंगलौर के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।	सं० एल०-12011/66/78-डी० 2 (ए) दिनांक 14/27-7-78 [संदर्भ संख्या 6/78 (केन्द्रीय)]।
26	कारपोरेशन बैंक लिमिटेड मंगलौर के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।	सं० एल०-12011/94/78-डी० 2 (ए) दिनांक 21/27-9-78 [संदर्भ संख्या 7/78 (केन्द्रीय)]।
27.	कुमार स्वामी आयरन और इन्वेस्टीगेशन नं० एम० डी० सी० पी० ओ० देवगिरि-583112 के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।	सं० एल०-26011/8/78-डी० 3 (बी) दिनांक 23-9-78 [संदर्भ सं० 8/78 (केन्द्रीय)]।
28.	विजय बैंक लिमिटेड बंगलौर के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।	सं० एल०-12011/101/78-डी० 2 (ए) दिनांक 7-10-78 [संदर्भ संख्या 9/78 (केन्द्रीय)]।
29.	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के० जी० एफ० के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र।	सं० एल०-43011/(3)/78-डी० 3 (बी) दिनांक 23/24-10-78 [संदर्भ नं० 10/78 (केन्द्रीय)]।
30.	मंगलौर हारबौर प्रोजेक्ट पनम्बूर के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र।	सं० एल०-45012(1)/77/डी० 4 (ए) दिनांक 24-10-78 [संदर्भ नं० 11/78 (केन्द्रीय)]।
31.	बैंक आफ बड़ोदा बंगलौर के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।	सं० एल०-12012/66/78डी० 2 (ए) दिनांक 29/11/78 1-12-78 [संदर्भ संख्या 12/78 (केन्द्रीय)]।

[सं० एल० 11025/4/79-डी० 4 (बी)]

नन्द लाल, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 15th June, 1979

S.O. 2468.—Whereas the industrial disputes specified in the Schedule hereto annexed are pending before Shri F. L. Alvares, the Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bangalore;

And, Whereas, the services of Shri F.L.F. Alvares are no longer available;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A read with sub-section (1) of the Section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal, the Presiding Officer of which shall be Shri H. Shanmukhappa with Headquarters at Bangalore and withdraws the proceedings in relation to the said disputes pending before the said Shri F.L.F. Alvares, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bangalore and transfers the same to Shri H. Shanmukhappa, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bangalore with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	Parties to the dispute	Reference No. and Date
1	2	3
1.	Workmen & the Management of M/s. Tungabhadra Minerals(P) Ltd., Taranagar P.O., Sandur Tk., Bellary District.	No. L.29011/40/73-LR. IV dated 29-9-73 [Ref. No./4/73 (Central)]

1	2	3
2.	Between the Management of Shri R. Muniswamy, Raising Contractor of B.R.H. Iron Ore Mines of M/s. Dalmia International, Hospet, and their workmen.	No. L-26012/6/73-LR. IV(ii) dt. 14-1-74 [Ref. No. 1/74 (Central)]
3.	Between the Management of Sri M. Raman, Raising Contractor of B.R.H. Iron Ore Mines of M/s. Dalmia International, Hospet and their workmen.	No. L-25012/6/73-LR IV (i) dt. 14-1-74 [Ref. No. 2/74 (Central)]
4.	Between the employers in relation to the Reserve Bank of India and their Workmen.	No. L-12025(20)/72. LR.III dt. 10-1-74 [Ref. No. 3/74 (Central)]
5.	Workmen & Management of M/s. Dalmia International, Hospet, Bellary Dt.	No. L-29012/5/74-L.R. IV dated 23-1-74 [Ref. No. 4/74 (Central)]
6.	Workmen & Management of M/s. Dalmia International, Hospet, Bellary Dt.	No. L-26012/8/74-LR. (IV) dated 21-10-74 [Ref. No. 5/74 (Central)]
7.	Workmen & Management of M/s. Dalmia International, Hospet, Bellary Dt.	No. L-26011/12/74-LR. IV dated 25-10-74 [Ref. No. 6/74 (Central)]
8.	Workmen & Management of M/s. Dalmia International, Hospet, Bellary Dt.	No. L-26012/4/74-LR. IV dated 15-11-74 [Ref. No. 7/74 (Central)]
9.	Workmen & Management of B.R.H. Iron Ore Mines of M/s. Dalmia International, Hospet, Bellary Dt.	No. L-26011/8/74-LR. IV dt. 21-12-74 [Ref. No. 1/75 (Central)]
10.	Workmen & Management of B.R.H. Iron Ore Mines of M/s. Dalmia International, Hospet, Bellary Dt.	No. L-26012/6/74-LR. IV Dt. 10-1-75 [Ref. No. 2/75 (Central)]
11.	Workmen & Managment of Bharata Rayana Haruvu Iron Ore Mines of M/s. Dalmia International Hospet.	No. L-26011/13/74-LR. IV D. 2 B. Dt. 27-1-75 [Ref. No. 3/75 (Central)]
12.	Workmen & Management of Bharat Gold Mines Ltd., Oorgam, K.G.F.	No.L.29012/9/74. LR. IV (D.O.3 B Dt. 26-2-75 [Ref. No. 4/75 (Central)]
13.	Workmen & Management of Bharat Gold Mines Ltd., Oorgam, K.G.F.	No. L-29012/25/74-LR. IV Dt. 3-3-75 [Ref. No. 5/75 (Central)]
14.	Workmen & Management of M/s Dalmia International, Hospet	No.L-26012/9/75-D. IV (B) Dt. 13-8-75 [Ref. No. 8/75 (Central)]
15.	Workmen & Management of M/s Dalmia International, Hospet	No. L-26012/10/75-D. IV(B) Dt. 26-8-75 [Ref. No. 9/75 (Central)]
16.	Workmen & Management of Syndicate Bank, Manipal	No. L-12012/18/73-LR. III(B) Dt. Sept., 75 [Ref. No. 10/75 (Central)]
17.	Workmen & Management of Doddakanya Magnesite Mine of M/s Tata Iron & Steel Co. Ltd., Mine Division, Noamundy	No. L-29011/3/76-D III (B) Dt. 17-3-76 [Ref. No. 2/76 (Central)]
18.	Workmen & Management of Vijaya Bank Ltd., Bangalore.	No.L-12012/85/76-D.II (A) Dt. 19-8-76 [Ref. No. 6/76 (Central)]
19.	Workmen & Management of Bharat Gold Mines Ltd., K.G.F.	No. L-43012/6/76. D. IV(B) Dated 3-9-76 [Ref. No. 7/76 (Central)]
20.	Workmen & Management of Life Insurance of India, Bangalore.	No. L-17011(7)/76-D. IV(A) dated 18-10-76 [Ref. No.9/76 (Central)]
21.	Workmen & Management of National Insurance Co. Ltd., Bangalore.	No. L-17012(3)/75-D. II (A) Dated 5-7-76 [Ref. No. 3 of 1977 (Central)]
22.	Workmen & Management of Karnataka Bank Ltd., Bangalore.	No. L-12012/2/78. D. II(A) Dt. 28-3-78 [Ref. No. 1/78 (Central)]
23.	Workmen & Management of Ramagiri Gold Mines Project—M/s. Bharat Gold Mines, Ramagiri.	No. L-43011/2/78-D. III(B) Dated 4-7-78 [Ref. No. 4/78 (Central)]
24	Workmen & Management of Karnataka Bank Ltd., Bangalore.	No. L-12011/6/78. D. II(A) Dt. 23-8-78 [Ref. No. 5/78 (Central)]
25.	Workmen & Management of Karnataka Bank Ltd., Mangalore.	No. L-12011/66/78-D. II(A) Dt.14/24-7-78 [Ref. No. 6/78 (Central)]
26	Workmen & Management of Corporation Bank Ltd., Mangalore.	No. L-12011/94/78-D. II(A) Dt. 21/27-9-78 [Ref. No. 7/78 (Central)]
27.	Workmen & Management of Kumaraswamy Iron Ore Investigation, No. M.D.C. P.O. Deogiri-583112.	No. L-26011/8/78-D. III (B) Dt. 23-9-78 [Ref. No. 8/78 (Central)]
28.	Workmen & Management of Vijaya Bank Ltd., Bangalore.	No. L-12011/101/78-D. II(A). Dt. 7-10-78 [Ref. No. 9/78 (Central)]
29.	Workmen & Management of Bharat Gold Mines Ltd., K.G.F.	No. L-43011(3)/78-D. III (B) Dt. 23/24-10-78 [Ref. No. 10/78 (Central)]
30.	Workmen & Management of Managalore Harbour Project, Panambur	No. L-45012(1)/77-D.IV (A) Dt. 24-10-78 [Ref. No. 11/78 (Central)]
31.	Workmen & Management of Bank of Baroda, Bangalore.	No. L-12012/66/78-D. II (A) Dt. 29-11-78/1-12-78 [Ref. No. 12/78 (Central)]

[F. No. S. 11025(4)/79-D.IV(B)]

NAND LAL, Desk Officer

New Delhi, the 5th July, 1979

S.O. 2469.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the industrial Tribunal, Bhubaneswar in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Reserve Bank of India, Bhubaneswar and their workmen over non-payment of overtime allowance to class IV staff workmen of their Bhubaneswar branch who were put on 16 hours duty from 1-10-1969 to 10-11-1972, which was received by the Central Government on 22-6-79.

INDUSTRIAL TRIBUNAL, BHUBANESWAR

Industrial Dispute Case No. 3 (Central) of 1978

Dated Bhubaneswar, the 18th June, 1979

BETWEEN

The employers in relation to the management of Reserve Bank of India, Bhubaneswar ... First Party

AND

Their Workmen ... Second Party

APPEARANCES :

Shri R. Srinivasan, Deputy Legal Advisor, Reserve Bank of India. ... For the first-party

Shri Sachidananda Mishra President, Reserve Bank Workers' Union, Bhubaneswar. ... For the second-party

AWARD

In exercise of the powers conferred by Section 7-A read with Clause (d) of Sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government in the Ministry of Labour has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication in its Order No. F. No. L-12011/63/77-D. II. A. dated 22nd/30th June, 1978 :

"Whether the action of the management of the Reserve Bank of India, Bhubaneswar in denying payment of overtime allowance to Peons-cum-Durwans of their Bhubaneswar Branch who were put on 16 hours duty from 1-10-1969 to 10-11-72 is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

2. The first-party management filed a written-statement, the gist of which is as follows :—

The Peon-cum-Durwans were appointed in the Agricultural Credit Department of the Reserve Bank of India which was housed in a small office at Bhubaneswar as it was considered unnecessary to have full time Durwans. As a measure of general safety the Peon-cum-Durwan is required to lock up the premises after regular office hours and stay or rest within the premises during night till the office hours of the next day. No duty or work was to be performed by them. As a compensation a Peon-cum-Durwan was being paid a special (functional) allowance in addition to the usual salary and other allowances to which he was entitled. There were previously settlements between the management and the All-India Reserve Bank Workers' Federation, to which the Bhubaneswar Branch was affiliated, regarding various matters. The method of compensating the Peon-cum-Durwans was successively accepted and dealt with. The claim of the Bhubaneswar Branch is belated. There was also an increase in the special (functional) allowance to Rs 45/- per month irrespective of the number of days in a month for which a Peon-cum-Durwan actually works. So it is prayed to reject the reference.

3. The Union had filed a written-statement completely denying the case of the management. Their case is that as the Peon-cum-Durwans were being employed beyond office hours also, they were entitled to overtime allowance as they were working for 16 hours. In fact, the management realised their mistake and the Bank's management as Bhubaneswar prepared statements with respect to the concerned Peon-cum-Durwans as to how many days they had worked for 16 hours between 1st October, 1969 to 10th November, 1972. So they claim that they should be given overtime allowance.

4. The Union also filed an additional written-statement in which it is stated that the Peon-cum-Durwans were a seperate category of employees whose services could be utilised as Peon-cum-Durwans whenever required. For all practical purposes they were watch and ward staff when they were required to guard the premises beyond office hours.

5. The management also filed an additional written-statement denying the allegations of the Union. It is their claim that since the subject matter of the dispute was arleary settled previously which was in force, there could not be any reference to this Court.

6. On these averments, the following issues can be framed :—

(1) Whether the Peon-cum-Durwans are entitled to overtime allowance for doing 16 hours duty from 1-10-1969 to 10-11-1972 ?

(2) Whether an industrial dispute can be raised when a previous settlement is in existence ?

(3) To what relief the workmen are entitled ?

7. Issue No. 1—Whether the Peon-cum-Durwans are entitled to overtime allowance for doing 16 hours duty from 1-10-1969 to 10-11-1972 and Issue No. 2—Whether an industrial dispute can be raised when a previous settlement is in existence ?

Issue Nos. 1 and 2 can be conveniently dealt with together. The management examined two witnesses while the Union examined three witnesses. According to M. W. 1, the duty of the Peon-cum-Durwan is simply to lock up the premises and stay inside the premises till the nextday. The intention for staying in the premises was only for the general safety. The M. W. 2 also speaks in the same line. He says that in the agreement Ext. 1, the Peon-cum-Durwan is compensated by payment of a special (functional) allowance. The Ext. 1 shows that the settlement, Ext. 1, would come into force from 1st November, 1964 and would apply to all centres where such arrangement for posting of the Peon-cum-Durwan was made and to be made in future. He also proves Ext. 2 which is the printed compilation of the settlements between the management and the union. The relevant entry is at page 6. It shows that the special (functional) allowance including night duty allowance to Peon-cum-Durwans at Jaipur, Gauhati and Ahmedabad will be Rs. 40 per month. It is not denied that the Union at Bhubaneswar is affiliated to the All-India Reserve Bank Workers' Federation. Even if there is no mention of Bhubaneswar in Ext. 2 at page 6, it definitely applies to Bhubaneswar Branch also. In his cross-examination the M. W. 2 states that if anything happens during the duty hours of a Peon-cum-Durwan, then it is his duyt as an employee of the Bank to report about it to the higher authorities. He further stated to the question by the court that there is no difference between the scales of pay and allowance of the Peons and the Peon-cum-Durwans and if the regular Peons work overtime, they are paid overtime allowance. A Peon-cum-Durwan works as a Peon in the office when he is not duty, but a Peon cannot be appointed as a Peon-cum-Durwan. Hence the post of a Peon is different from that of a Peon-cum-Durwan.

7. The W. W. 1 had stated that he joined the Reserve Bank of India on 1-10-1962 as a Peon and if a Peon-cum-Durwan was going on leave, he was acting in his place and he was being paid overtime allowance. So it is clear that only when a Peon was appointed as a Peon-cum-Durwan in case a Peon cum-Durwan goes on leave, then only he is being paid overtime allowance. This is also clear from his statement in cross-examination wherein he states that he was the only person who was paid the overtime allowance and that he was not a regular Peon-cum-Durwan. He further states that Akruna Mangaraj, Dharanidhar Nayak and Sanatan Nayak regular Peon-cum-Durwans and they were paid only their salaries and some special (functional) allowance in addition to their salaries. The W. W. 2 was appointed as a Peon-cum-Durwan. He speaks about the duties which he was performing. He also complained regarding the non-payment of overtime allowance which has been marked as Ext. P. He was informed that the payment of overtime allowance would be considered. In para 4 of his cross-examination he has stated that the ordinary Peons and others were being paid overtime allowance for work done beynd 8 hours and the others were not being paid special (functional) allowance. The W. W. 3 worked as a Peon-cum-Durwan for one month and he speaks about the duties he was performing as such. He says in his cross-examination that when he was working he got allowances as every Peon-cum-Durwan was getting and he was also getting overtime allowance.

8. The management submits that as the Desai Award is still in force, it is not open to the second-party to raise a dispute. There were also bipartite settlements dated 8-2-65, 7-2-1967 and 27-11-1970 between the parties and so there cannot be any industrial dispute as the dispute was covered by a settlement. He relied on the Law of Industrial Disputes by Malhotra at page 412 and also 74 C.W.N. 1002. There cannot be any dispute with respect to this point of law. It was further submitted on behalf of the mangement that this is a belated dispute raised by the union and so the reference should not have made as the dispute has become stale. The management relied on the cases reported in 1961-II L.L.J. 89, 1964-I L.L.J. 622, 1959-II L.L.J. 26 and 1970-II LLJ 256. On behalf of the Union it was submitted that there cannot be any such limitation as urged by the management and they relied on the case reported in 1968-I L.L.J. 6. The respective conetntions raised by the parties on this point cannot be disputed. There should be a reasonable time for raising a dispute and it cannot be said that at any time means any length of time.

9. Since the Peon-cum-Durwans are paid special (functional) allowance which is not being paid to any other cate-

gory of Peons, it cannot be said that they are also entitled to overtime allowance because the duty of the Peon-cum-Durwans is definitely to work beyond office hours also and their very designation indicates the same. The Union has relied on the case reported in 1966-II L.L.J. 194 and submitted that the designation of a particular category of workers is not material but the Tribunal has to see the work done by them. That is why I feel that the Peon-cum-Durwans are a special category of Peons to whom functional allowance is being paid because of their duties and as such, they are not entitled to any overtime allowance. In the decision reported in A.I.R. 1967 Supreme Court 47 relied on by the Union it has been laid down that the Tribunal has to look into the pleadings of the parties to decide the dispute. That is what is being done in this case.

10. In the result, I find that the Peon-cum-Durwans of the Bhubaneswar Branch of the Reserve Bank of India cannot claim any overtime allowance for doing 16 hours duty from 1-10-1969 to 10-11-1972. The issues are answered accordingly.

11. Issue No. 3.—To what relief the workmen are entitled ?

In the result, I find that the second-party workmen are not entitled to any relief as claimed. The issue is answered accordingly.

12. The Award is passed accordingly.

M. V. GANGARAJU, Presiding Officer
[No. L-12011/63/77-D.II.A]

S.O. 2470.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal Bhubaneswar in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Allahabad Bank and their workmen over deduction of full days wages for the period of only 4 hours on 29-12-77, which was received by the Central Government on 22-6-79.

INDUSTRIAL TRIBUNAL, BHUBANESWAR.

Industrial Dispute Case No. 6 (Central) of 1978

Dated Bhubaneswar, the 18th June, 1979

BETWEEN

The employers in relation to the management of the Allahabad Bank. ... First Party

AND

Their workmen ... Second Party

APPEARANCES :

Shri M. R. Sarbadhikari,
Law Officer,
Allahabad Bank. ... For the first-party

Shri D. N. Nayak,
Advocate. ... For the second-party

AWARD

In exercise of the powers conferred by Section 7-A read with Clause (d) of Sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government in the Ministry of Labour has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication in its Order No. L-12011/62/78-D. II. A. dated 25th/26th October, 1978 :

"Whether the action of the management of Allahabad Bank is not allowing employees of their branches in the State of Orissa to join and perform their duties from 2 P.M. to 5 P.M. on 29-12-77 and to deny them wages for the whole of that day is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

2. The case of the first-party is as follows :—

The employees of all the nationalised Banks in India went on strike for four hours on 29-12-1977 from 10 A.M. to 2 P.M. The employees of the Allahabad Bank posted at different Branches in the State of Orissa also took part in the strike. They all came to the Bank at 10 A.M., signed the attendance register and went on strike.

3. A circular was issued by the Bank being circular No. 17/23/1068 dated 27-12-1977 that if any employee of the Bank would go on strike during the working hours of the Bank, then no salary would be paid. So the salary of the employees of the Bank for that period was withheld and as such, this industrial dispute was raised by them.

4. The case of the workmen is that the circular quoted in the written-statement of the management was illegal and violative of Section 9-A of the Industrial Disputes Act and it was in violation of the management's earlier circular No. 1036 dated 17-8-1977. The workmen performed their duties on 29-12-1977 from 2 P.M. till the rest of their duty period, and they were allowed to do so with the active knowledge and tacit consent of the management. So it is prayed that the action of the management should be disapproved.

5. The following issues can be framed on these pleadings :

(1) Whether the action of the management of the Allahabad Bank in not allowing the employees of their branches in the State of Orissa to join and perform their duties from 2 P.M. to 5 P.M. on 29-12-1977 and to deny them wages for the whole of that day is justified ?

(2) To what relief the workmen are entitled ?

6. Issue No. 1—Whether the action of the management of the Allahabad Bank in not allowing the employees of their branches in the State of Orissa to join and perform their duties from 2 P.M. to 5 P.M. on 29-12-1977 and to deny them wages for the whole of that day is justified ?

On behalf of the workmen the General Secretary of the All Orissa Allahabad Bank Employees' Union was examined and on behalf of the management the Area Manager, Allahabad Bank, Bhubaneswar, was examined. The W.W. 1 speaks about the case of the Union. He denies that the employees signed the attendance register at 10 A.M. as is the case of the management in support of which the management had field Exts. A and B, the copies of the attendance registers. In both the Exhibits it is stated that after signing the attendance register on the 29th, the employees went on strike. In Ext. B it is clearly stated that the workmen observed strike during the entire banking hours from 10 A.M. to 2 P.M. but all of them initialled the attendance register before going on strike. In the cross-examination the W.W. 1 has clearly stated that the All India Bank Employees' Co-ordination Committee, which is the parent organisation of the Orissa Union, did not accord any permission or authority for the Orissa Union to raise this dispute. He was not aware if any other similar dispute was pending before any Industrial Tribunal in any other State of the country. It is admitted by him that at the time of signing the attendance register, no time will be recorded. In para 7 the clearly states that the public transaction in the Bank takes place between 10 A.M. to 2 P.M. and are reduced into writing in various books.

7. On behalf of the management one witness was examined and he says that the salary of the workmen of all the Branches in Orissa of the Allahabad Bank was deducted for the whole day for 29-12-1977. Of course, he was not present at the spot on the day of the strike.

8. The argument advanced on behalf of the workmen is that the management was given sufficient notice before they went on strike and that it is the right of the workers to go on strike to press their demands. For this he relied on the case reported in A.I.R. 1960 Supreme Court 1258. Definitely the legal point laid down in that case must be accepted. But it is to be seen whether the action of the management in not paying the workers for the strike period is justified or not. In this connection the decision reported in 1979 (38) F.L.R. 295 is quite applicable to the facts of this case wherein it has been decided that no payment could be made for the period for which the workers absented themselves. Similarly, the decision reported in 1978-II L.L.J. 117 lays down the principle that the petitioner Bank had a right to make deduction without holding disciplinary proceedings, thus setting aside the view of the Labour Court in that case. Further, as the All India Union did not permit the Union of Orissa to raise the dispute, it was submitted that the Government should not have referred the matter to the Tribunal as no dispute

at all was raised by the employees before the management. For this, reliance is placed on the case reported in A.I.R. 1968 Supreme Court 529. Evidently in no other State a similar dispute was raised by the employees of the Allahabad Bank and as such, this decision is applicable to the facts of the present case.

9. On behalf of the workers reliance was placed on the case reported in 1961-II L.L.J. 89 which I feel is not at all applicable to the facts of the present case for payment of extra wages under Notification dated 15-11-1947 issued by the erstwhile Korea State Government as regards wages.

10. In the result I find that the management was quite justified in not paying the employees of their Branches in the State of Orissa the wages for the whole of that day and in not allowing them to perform their duties from 2 P.M. to 5 P.M. on 29-12-1977. It is an admitted fact that public transactions take place between 10 A.M. to 2 P.M., and if the employees do not do their duties for that period, they are not entitled to any wages for the entire day. The issue is answered accordingly.

10. Issue No. 2.—To what relief the workmen are entitled ?

In the result I find that the workmen are not at all entitled to any relief. The issue is answered accordingly.

11. The Award is passed accordingly.

M. V. GANGARAJU, Presiding Officer
[No. L-12011/62/78-D. II. A]
S. K. MUKERJEE, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1979

आदेश

का० आ० 2471.— वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, पेंच एरिया, परासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व भारतीय कोयला खदान संघ (बी० एम० एस०) छिंदवाड़ा करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निदेशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को, जो उसे 16 जून, 1979 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री सी० बी० जैन, एजेन्ट, न्यूटन चिकली ग्रुप ।

2. श्री आर० एल० शर्मा, कार्मिक प्रबन्धक, वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, पेंच एरिया, डाकघर परासिया, जिला छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री शिवबरन सिंह, अध्यक्ष

2. श्री बी० के० तिवारी, महामंत्री, भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ, डाकघर चांदामेटा

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित विवाद को श्री के० शरण, उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है ।

"पेंच एरिया में लोडिंग/रेजिंग मेटों द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए क्या यूनियन की यह मांग न्यायोचित है कि उन्हें एन० सी० डब्ल्यू० ए० के लिपिक ग्रेड 2 या किसी अन्य उपयुक्त उच्चतर वर्ग में रखा जाए या उन्हें विशेष भत्ता दिया जाय, यदि यह मांग न्यायोचित है, तो

1 उन्हें किस ग्रेड या उच्चतर वर्ग में रखा जाए ? या

2 उन्हें क्या भत्ता दिया जाए ?"

1. प्रबन्धतंत्र का नाम और पता	: वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, पेंच एरिया, डाकघर परासिया जिला छिंदवाड़ा (एम० पी०)
2. कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन का नाम और पता	भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ (बी० एम० एस०) डाकघर चांदामेटा, जिला छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)
3. अंतर्वलित प्रतिष्ठान	पेंच एरिया में सभी कोयला खानें ।
4. यूनियन का नाम	भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ (बी० एम० एस०)
5. उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या	15326 (1-5-1979 को)
6. विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या	177

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्ध कर होगा ।

मध्यस्थ अपना पंचाट तीन मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा ।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले	कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले
ह० - (सी० बी० जैन)	ह० -(शिवबरन सिंह)
ह० - (आर० एल० शर्मा)	ह० - (बी० के० तिवारी)

साक्षी

1. ह० -(अपठनीय)
2. ह० - (अपठनीय)

परासिया
तारीख 5-6-1979

[सं० एल-22013/6/79-डी० 4 (बी)]

शशि भूषण, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th July, 1979

ORDER

S.O. 2471.—Whereas an industrial dispute exists between the management of Western Coalfields Limited, Pench Area Parasia District Chhindwara, Madhya Pradesh and their workmen represented by Bhartiya Koyla Khadan Mazdoor Sangh (BMS) Chhindwara;

And whereas the said management and their workmen have by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration of the person mentioned therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which always received by the Central Government on 16th June 1979.)

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of the Parties :

Representing employers :	1. Shri C.B. Jain Agent, Newton Chickli Group 2. Shri R.L. Sharma, Personne Manager, Western Coalfields Ltd., Pench Area, P.O. Parasia, District, Chhindwara (M.P.)
Representing workmen :	1. Shri Shivbaran Singh President. 2. Shri B.K. Tiwari, General Secretary, Bhartiya Koyla Khadan Mazdoor Sangh P.O. Chandamatta.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri K. Saharan, Dy. Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi :

"Keeping in view the jobs done by Loading/Raising Mates in Pench Area, whether the demand of the union that they should be placed in Clerical Gr.II of N.C.W.A. or in any other appropriate higher category or they should be paid special allowance, is justified; if the demand is justified, then :

1. In what grade or higher category they should be placed ?

or

2. What allowance they should be paid ?"

1. Name and address of the management.	Western Coalfields Ltd. Pench Area, P.O. Parasia Dist. Chhindwara (M.P.)
2. Name and address of the union representing the workmen.	Bhartiya Koyla Khadan Mazdoor Sangh (BMS) P.O. Chandamatta Distt. Chhindwara (M.P.)
3. Establishment involved	All collieries in Pench Area
4. Name of the union	Bhartiya Koyla Khadan Mazdoor Sangh (BMS)
5. Total number of workers employed in the undertaking.	15326 (As on 1-5-79)
6. Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute.	177

We further agree that the decision of the Arbitrator shall be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of 3 months or within such further time as extended by mutual agreement between the parties in writing.

Signature of the Parties

Representing Employer : Sd/-(C.B. Jain)
Sd/-(R.L. Sharma)

Representing workmen Sd/-(Shivbaran Singh)

Witnesses :

(1) Sd/- (Illegible)
(2) Sd- (Illegible) Parasia
Dated 5-6-1979

Sd/- (B.K. TIWARI)
[No. L-22013/6/79-D. IV (B)]
SHASHI BHUSHAN, Desk Officer

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1979

का०आ० 2472.—नियात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की राय है कि भारत से निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि एल्यूमिनियम के बर्तनों को निर्यात में पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें नियात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम II के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार नियात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है;

अत. अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त उपनियम के अनुसरण में उक्त प्रस्तावों को, उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

2 सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहे तो वह उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर नियात निरीक्षण परिषद् 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' 14/1 बी एजरा स्ट्रीट (8वीं मंजिल) कलकत्ता 700001 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

(1) अधिसूचित करना कि एल्यूमिनियम के बर्तन निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे।

(2) इस आदेश के उपाबंध I में दिए गए एल्यूमीनियम के बर्तनों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1979 के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण के ऐसे क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व ऐसे एल्यूमीनियम के बर्तनों पर लागू किया जाएगा,

(3) (क) भारतीय या कोई अन्य राष्ट्रीय मानक को,

और

(ख) इस आदेश के उपाबंध (ii) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम विनिर्देशों के अधीन रहते हुए विदेशी क्रेता तथा निर्यातकर्ता के बीच निर्यात संविदा के सहमत विनिर्देशों के रूप में निर्यातकर्ता द्वारा घोषित विनिर्देशों को,

ऐसे एल्यूमीनियम के बर्तनों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना।

(4) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे एल्यूमिनियम के बर्तनों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरणों में से किसी एक के द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि एल्यूमीनियम के बर्तनों के प्रेषण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं तथा निर्यात योग्य है।

3. इस आदेश की कोई बात भावी क्रेताओं को भूमि समुद्री या वायु मार्ग द्वारा एल्यूमीनियम के बर्तनों के वास्तविक नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी।

4. इस आदेश में 'एल्यूमीनियम के बर्तनों' से अभिप्रेत है एल्यूमीनियम या इसकी मिश्र धातु पिटवां या ढलवां ऐल्यूमीनियम से विनिर्मित कोई बर्तन जिसका उपयोग बर्तनों के रूप में किया जा सकता है।

उपाबंध I

नियात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप।

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एल्यूमीनियम के बर्तनों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है।

(ख) 'अभिकरण' से नियम की धारा 7 के अधीन बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली, मद्रास में स्थापित कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है।

(ग) 'ऐल्यूमीनियम के बर्तनों' से अभिप्रेत है एल्यूमीनियम या इसकी मिश्र धातु, पिटवां या ढलवां एल्यूमीनियम से विनिर्मित कोई बर्तन जिसका उपयोग बर्तन के रूप में किया जा सकता है।

3. क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण:—

(1) क्वालिटी नियंत्रण :—निर्यात के लिए आशयित एल्यूमीनियम के बर्तनों या क्वालिटी नियंत्रण यह देखने के विचार से किया जाएगा कि वे इससे उपबंधित अनुसूची में दिए गए नियंत्रण के स्तरों के साथ विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रमों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करने हुए अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है, अर्थात :—

(i) खरीदी गई सामग्री तथा घटक नियंत्रण :—

(क) प्रयोग की जाने वाली सामग्री या घटकों के गुण-धर्मों को समाविष्ट करते हुए विनिर्माता क्रय विनिर्देश अधिकथित करेगा तथा आने वाले माल की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण या परीक्षण के पर्याप्त साधन रखेगा।

(ख) स्वीकृत परेषणों के साथ या तो प्रदाय कर्ता का परीक्षण या निरीक्षण प्रमाणपत्र होगा जिसमें क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं की पुष्टि की जाएगी जिस दशा में उक्त परीक्षण या निरीक्षण प्रमाण-पत्रों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए विनिर्माता प्रदायकर्ता के लिए क्रेता द्वारा कालिक जांच (अर्थात एक ही माल के एक ही प्रदाय कर्ता के लिए प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक तीन मास में एक बार की जाएगी) या खरीदी गई सामग्री या घटकों का या तो कारखाने की प्रयोगशाला में या परीक्षण गृह में नियमित रूप से निरीक्षण या परीक्षण किया जाएगा।

(ग) किए जाने वाले निरीक्षण या परीक्षण के लिए नमूना लेना सांख्यिकी अन्वेषण पर आधारित होगा।

(घ) निरीक्षण या परीक्षण किए जाने के बाद स्वीकृत तथा अस्वीकृत माल या घटकों को पृथक करने के लिए तथा अस्वीकृत माल या घटकों के संचयन के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी।

(ङ) ऊपर विनिर्दिष्ट नियंत्रणों के संबंध में पर्याप्त अभिलेख विनिर्माता द्वारा नियमित तथा व्यवस्थित ढंग से रखे जायेंगे।

(ii) प्रक्रिया नियंत्रण :—

(क) विनिर्माता विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए ब्योरेवार प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित करेगा।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देश में अधिकथित प्रक्रियाओं के नियंत्रण के लिए उपस्कर, उपकरण एवं साधनों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणों के सत्यापन की संभावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता यथोचित अभिलेख रखेगा।

(iii) उत्पाद नियंत्रण :—

(क) अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद की जांच करने के लिए विनिर्माता के पास या तो स्वयं अपनी यथोचित परीक्षण सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच वहां तक होगी जहां ऐसी परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हों।

(ख) परीक्षण के लिए नमूना लेना (जहां कहीं अपेक्षित हो) सांख्यिकी पर आधारित होगा।

(ग) किए गए परीक्षणों के संबंध में विनिर्माता द्वारा यथोचित अभिलेख नियमित रूप से रखे जायेंगे।

(iv) परिरक्षण नियंत्रण :—

(क) विनिर्माता उत्पाद को मौसमी दशाओं के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित करने के लिए ब्योरेवार विनिर्देश अधिकथित करेगा।

(ख) उत्पाद को भंडारीकरण तथा अभिवहन, दोनों, के दौरान अच्छी तरह से परिरक्षित किया जाएगा।

(v) मौसम संबंधी नियंत्रण :—

उत्पादन तथा निरीक्षण में प्रयुक्त प्रभावी और उपकरणों की कालिक जांच या अंशशोधन किया जाएगा और विनिर्माता द्वारा वृत्तकार्य के रूप में अभिलेख रखे जायेंगे।

(vi) पैकिंग नियंत्रण :—

विनिर्माता निर्यात किये जाने वाले पैकेजों के लिए ब्योरेवार पैकिंग विनिर्देश बनाएगा तथा उनका पूर्णतया पालन करेगा।

(2) निरीक्षण :—निर्यात के लिए आशयित एल्यूमीनियम के बर्तनों का निरीक्षण परेषणों में से नमूना लेकर उनकी इस दृष्टि से परीक्षा और परीक्षण करने के लिए किया जाएगा कि परेषण अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण का आधार :—निर्यात के लिए आशयित एल्यूमीनियम के बर्तनों का निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जाएगा कि वे—

या तो

(क) यह सुनिश्चित करते हुए विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान नियम 3 के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट क्वालिटी नियंत्रण अभ्यासों का प्रयोग किया गया है,

या

(ख) नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसार किए गए निरीक्षण के आधार पर

या

(ग) दोनों द्वारा,

अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है।

5. निरीक्षण की प्रक्रिया: (क) एल्यूमिनियम के बर्तनों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता अपने ऐसा करने के आशय की लिखित सूचना किसी भी एक अभिकरण को देगा तथा ऐसी सूचना के साथ एक या तो यह घोषणा देगा कि एल्यूमिनियम के बर्तनों का परेषण नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियंत्रणों के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण उपायों का प्रयोग करते हुए बनाए गए है या बनाए जा रहे है तथा परेषण प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है या निर्यात संविदा में वर्णित विनिर्देशों की घोषणा सभी तकनीकी विशेषताओं के ब्यौरे देते हुए देगा जिससे अभिकरण नियम 5 के उपनियम (2) के अनुसार निरीक्षण करने में समर्थ हो सकें।

(ख) निर्यातकर्ता उसी समय ऐसी सूचना की एक प्रति परिषद् के निकटतम कार्यालय को देगा। परिषद् के कार्यालयों के पते निम्नलिखित हैं :—

मुख्य कार्यालय	निर्यात निरीक्षण परिषद्, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर (8वीं मंजिले), 14, 1वी एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता—700001
क्षेत्रीय कार्यालय	(1) निर्यात निरीक्षण परिषद् अमन चैम्बर्स (5वीं मंजिल) 113 महर्षि कार्वे रोड, बम्बई 400004
	(2) निर्यात निरीक्षण परिषद्, मनोहर बिल्डिंग्स, महात्मा गांधी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन 682011
	(3) निर्यात निरीक्षण परिषद् म्युनिसिपल मार्केट बिल्डिंग, 3 सरस्वती मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 110005

(2) निर्यातकर्ता अभिकरण को परेषण पर लगाए गए पहचान चिन्ह भी देगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा निर्यातकर्ता के परिसर से या विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम सात दिन पहले अभिकरण के कार्यालय में पहुंचेगी।

(4)(क) उपनियम (1) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर, अभिकरण नियम, 4 के अधीन यथा उपबन्धित के अनुसार किए गए निरीक्षण तथा इस संबंध में परिषद् द्वारा जारी किए गए अनुदेश, यदि कोई हों, के आधार पर अपना यह समाधान कर लेने पर कि परेषण का विनिर्माण इस पर लागू मानक विनिर्देशों के अनुसार किया गया है सात दिनों के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि एल्यूमिनियम के बर्तनों का परेषण निर्यात योग्य है।

परन्तु जहां अभिकरण का समाधान नहीं हुआ है वहां वह सात दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की, उसके कारणों सहित सूचना देगा।

(ख) ऐसे मामलों के सिवाय जहां निर्यातकर्ता स्वयं एल्यूमिनियम के बर्तनों का विनिर्माता हो तथा निरीक्षण नियम 4 के उप खण्ड (क) या (ग) के उपबन्धों के अनुसार किया गया है अन्य सभी मामलों में निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात् अभिकरण तत्काल यह सुनिश्चित करने के लिए परेषण के पैकेजों को इस ढंग से सीलबंद करेगा कि सीलबंद माल के साथ छेड़-छाड़ न की जा सके। परेषण की अस्वीकृति की दशा में, यदि निर्यातकर्ता ऐसा चाहे तो परेषण को अभिकरण द्वारा सीलबन्द नहीं किया जा सकता है। तथापि, ऐसे मामलों में निर्यातकर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा।

6. निरीक्षण का स्थान:—इन नियमों के प्रयोजनों के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का निरीक्षण।

(क) विनिर्माता के परिसर पर,

या

(ख) उस परिसर पर किया जाएगा जहां निर्यातकर्ता एल्यूमिनियम के बर्तनों का परेषण निरीक्षक के लिए प्रस्तुत किया जाता है परन्तु यह तब जब कि वहां जांच तथा निरीक्षण के प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

7. निरीक्षण फीस:—इन नियमों के अधीन प्रत्येक परेषण के लिए पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक एक सौ रुपये के लिए पचास पैसे की दर से फीस प्रत्येक परेषण के लिए न्यूनतम पचास रुपये के अधीन रहते हुए, निरीक्षण फीस के रूप में निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को दी जाएगी।

8. अपील:—(1) नियम 5 के उपनियम (4) के अधीन प्रमाण पत्र देने से अभिकरण द्वारा इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक सात व्यक्तियों के अपील पैनल को अपील कर सकेगा।

(2) पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निपटायी जायेगी।

उपाबंध-11

(पैरा 1 का उपपैरा (3) देखिए)

एल्यूमिनियम के बर्तनों लिए न्यूनतम विनिर्देश

1.0 सामग्री:

1.1 पिटवां या ढलवां एल्यूमिनियम के बर्तनों की एल्यूमिनियम की मात्रा 99.0 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

1.2 पिटवां या ढलवां एल्यूमिनियम धातु के बर्तनों के लिए रासायनिक मिश्रण निर्यातकर्ता तथा विदेशी क्रेता के बीच निर्यात संविदा में हुई सहमति के अनुसार होगा। किसी भी ऐसे विशिष्ट अनुबंध के न होने पर सामग्री ऐसे किसी भी राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होगी जो नवीनतम हो।

1.3 बर्तनों की मोटाई निर्यातकर्ता तथा विदेशी क्रेता के बीच हुए करार के अधीन होगी।

2.0 आकार तथा विमाएं

बर्तनों के आकार तथा विमाएं निर्यातकर्ता तथा विदेशी क्रेता के बीच हुए करार के अधीन होंगे। निम्नलिखित सह्यता विमाओं के लिए लागू होगी।

से अधिक	तक तथा सहित	सह्यता
मि०मि०	मि०मी०	मि०मि०
30	30	±1
30	100	±2
100	200	±3
200	—	±5

3.0 कार्य कौशल तथा फिनिश:

बर्तनों के किनारे धार वाले नहीं होंगे। उनकी फिनिश चारों तरफ से चमकीली होगी। परिचालित बर्तन दरारों, सिलवटों, सिकुड़नों, सिकुड़ियों, गढ़ों, खरोंचों, गहरा औजार के गहरे निशानों तथा अन्य सतही दोषों से मुक्त होंगे।

4.0 परीक्षण :

4.1 पानी रिसने का परीक्षण:— बर्तन में किनारे तक पानी से भरने के बाद बर्तन कहीं से रिसना नहीं चाहिए।

4.2. मोड़ परीक्षण:— पिटवां एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए प्रयोग की गई सामग्री का नमूना 1800 कोण से मोड़ा जाएगा और बहुत नजदीक से हथौड़ा मारा जाएगा जिससे नमूना टूटेगा नहीं या दरार का चिन्ह नहीं पड़ेगा। ऐसे मामलों में जहां शर्त विशेष रूप से अनुबद्ध है मोड़ परीक्षण किसी राष्ट्रीय मानक के नवीनतम विवरण के अनुसार किया जाएगा। ऐसे खुले हुए एल्यूमिनियम के बर्तनों तथा पिटवां एल्यूमिनियम के बर्तनों पर जिनकी चद्दर की मोटाई 2.6 मि० मी० (12 एस डब्ल्यू जी) से अधिक है, मोड़ परीक्षण लागू नहीं होगा।

4.3. सीसा तथा बिस्मथ अंश परीक्षण:- बर्तनों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री में सीसा तथा बिस्मथ प्रत्येक के अंश 0.05 से अधिक नहीं होंगे।

4.4. ऐनोडी लेपका मोटाई परीक्षण :— बर्तन पर ऐनोडी लेप की मोटाई जब मानक निरावृत पद्धति द्वारा निर्धारित की गई हो आई एस 1868 : 1968 (या इसके नवीनतम विवरण) के अनुसार 5 माईक्रोन से नहीं होगी। यह परीक्षण केवल ऐनोड किए गए बर्तनों पर लागू होगा।

5.0. चिह्नांकन :—

जब तक विदेशी क्रेता द्वारा अन्यथा अनुबंध न किय गया हो बर्तन के तल पर विनिर्माता का नाम, व्यापार चिह्न या पहचान चिह्न संपाठ्य रीति में इस रीति से चिन्हित किए जाएगें कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चिह्न का निशान दूसरी तरफ न उभर आए।

6.0. पैकिंग

6.1. पकेज की फिनिश अच्छी तरह की जाएगी देखने में सुन्दर होगा

6.2. पैकेज के भीतरी अन्तर्वस्तुओं को इस प्रकार से पैक किया जाएगा कि ये निम्नलिखित परीक्षणों में ठीक रह सकें।

6.2.1. निपात परीक्षण (सिर भार के लिए कुल भार केवल 37 किलो ग्राम तक) एक पैकेज 90 मि० मी० की उचाई से एक बार सबसे बड़ी समतल सतह पर, एक बार सबसे लम्बे किनारे पर तथा एक बार इसके किसी भी किनारे पर गिराया जाएगा।

6.2.2. लोटन (रोलिंग) परीक्षण कुल भार केवल 500 कि० ग्राम तक) लोटन पैकज इसके छह (6) मीटर आगे तरफ या छह(6) मीटर पीछे की तरफ या बारह मीटर केवल एक ही दिशा में लुढ़काया जाएगा।

6.2.3. जल फुहार परीक्षण:- (पैकेज के प्रत्येक डिजाइन के लिए) पैकेज की पानी की फुहार में जो अकस्मात आई वर्षा की बौछार के बराबर हो 5 मिनट तक खोलकार रखा जाएगा।

7.0 नमूना लेना तथा अनुरूपता की कसौटी

7.1 प्रत्येक परेषण के निरीक्षण के लिए नमूना लेना तथा अनुरूपता के लिए कसौटी नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगे ।

7.2. किसी भी परेषण में, एक ही सामग्री और डिजाईन के सभी बर्तनों को आकर पूर ध्यान दिए बिना एक साथ इकट्ठा करके एक लाट बनाया जाएगा। किन्तु विनाशात्मक परीक्षण में सामग्री के एक ही बैच से विनिर्मित सभी प्रकार और आकार के बर्तन इकठ्ठा करके एक लाट बनाया जाएगा।

सारणी

(1)	(2)		(3)	
लाट आकार	नमूना आकार		दोष युक्तों की अनुमेय संख्या	
	खंड 2.0,3.0,5.0. 6.0 तथा उपखंड 4.1 के लिए	उपखंड 4.2,4.3 तथा 4.4 के लिए	स्तम्भ (2) के क के लिए	स्तम्भ (2) के ख के लिए
	क	ख		
15 तक	2	1	0	
16 से 25 तक	3	1	0	
26 से 100 तक	5	1	0	
101 से 150 तक	8	2	0	
151 से 300 तक	13	2	0	कुछ नहीं
301 से 500	20	3	1	
501 से 1000 तक	32	3	2	
1001 से 3000 तक	50	4	3	
3001 से ऊपर	80	5	5	

अनुसूची

(नियम 3 देखिए)

क्रम सं०	परीक्षण /निरीक्षण विशेषताएं	अपेक्षाएं	परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की सं०	लाट आकार/आवृत्ति	टिप्पणियां
1.	सामग्री				
	(1) रसायनिक मिश्रण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	एक	कच्चे माल के प्रत्येक कास्ट/ढोठ के लिए	जब कभी उत्पादक के प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थन किया जाए, इन विशेषताओं का सत्यापन पांच परीक्षणों में कम से कम एक बार किया जाएगा ।
	(2) यांत्रिक गुण				
2.	उत्पादन के दौरान नियंत्रण				
	(1) कार्यकौशल तथा परिसाधन	यथोक्त	प्रत्येक	एक ही प्रकार और आकार के उत्पाद के प्रत्येक बैच के लिए	
	(2) विमाएं	यथोक्त	एक	पहला आफ नमूना और उसके बाद प्रत्येक तथा आकार की हर पचासवीं संख्या	
3.	ऐनोडीकरण, यदि लागू हो				
	(क) परिसाधन	यथोक्त	प्रत्येक	एक ही प्रकार तथा आकार के उत्पाद का प्रत्येक बैच	
	(ख) लेप की मोटाई	यथोक्त	एक	यथोक्त	
	(ग) अन्य कोई परख	यथोक्त	एक	यथोक्त	
4.	पैकिंग नियंत्रण				
	(1) निपात परीक्षण	यथोक्त	एक	प्रत्येक परेषण	
	(2) लोटन परीक्षण	यथोक्त	एक	यथोक्त	
	(3) जल फुहार परीक्षण	यथोक्त	एक	पैकेज का प्रत्येक डिजाईन	

[सं० 6(3)/79-ई०आई एंड ईपी]

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 14th July, 1978

S.O. 2472 .—Whereas the Central Government is of opinion that, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient so to do for the development of export trade of India that aluminium utensils shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

And, whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule II of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 ;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward and objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within forty five days or the date of publication of this order in the official Gazette to the Export Inspection Council, World Trade Centre (7th Floor), 14/1B, Ezra Street, Calcutta-700001.

PROPOSALS

(1) To notify that aluminium utensils shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) To specify the type of inspection in accordance with the draft Export of Aluminium Utensils (Quality Control and Inspection) Rules, 1979 set out in Annexure—I to this order as the type of quality control and inspection which would be applied to such aluminium utensils prior to export ;

(3) to recognise —

(a) Indian or any other national standard, and

(b) the specifications declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract between the foreign buyer and the exporter subject to the minimum specification set out in Annexure II to this order—

as the standard specification for such aluminium utensils.

(4) To prohibit the export in the course of international trade of any such aluminium utensils unless the same are accompanied by a certificate issued by any one of the agencies established by the Central Government under Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the consignments of aluminium utensils satisfy the conditions relating to quality control and inspection and are exportworthy.

3. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of bonafide sample of aluminium utensils to prospective buyers.

4. In this order "aluminium utensils" shall mean any utensil manufactured from aluminium or its alloys, wrought and cast, which can be used as utensils.

ANNEXURE I

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Export of Aluminium Utensils (Quality Control and Inspection) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of publication in Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(b) "Agency" means any one of the agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under Section 7 of the Act.

(c) "Aluminium utensils" means any utensil manufactured from aluminium or its alloys, wrought or cast, which can be used as an utensil.

3. Quality Control and Inspection.—(1) Quality Control:—The quality control of the aluminium utensils intended for export shall be done with a view to see that the same confirms to the specifications recognized by the Central Government under section 6 of the Act by effecting the following controls at different stages of manufacture together with the levels of control as given in the Schedule annexed hereto, namely :—

(i) Boughout materials and components control :—

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used and shall have adequate means of inspection or testing to ensure conformity of the incoming lots.

(b) The accepted consignments shall be either accompanied by a supplier's test or inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specifications, in which case occasional checks (that is to say once in each quarter of the year for the same supplier of the same material) shall be conducted by the manufacturer for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test or inspection certificates, or the purchased materials or components shall be regularly inspected or tested either in a laboratory in the factory or in some other laboratory or test house.

(c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be based on a recorded investigation.

(d) After the inspection or test is carried out, systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials or components and in disposal of rejected materials or components.

(e) Adequate records in respect of the above mentioned controls shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(ii) Process Control :—

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturer for different processes of manufacture.

(b) Equipments, instrumentation and facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process specifications.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacturer to ensure the possibility of verifying the controls exercised during the process of manufacture.

(iii) Product Control :—

(a) The manufacturer shall either have his own adequate testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the specifications recognised under section 6 of the Act.

(b) Sampling (wherever required) for testing shall be based on a recorded investigation.

(c) Adequate records in respect of tests carried out shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(iv) Preservation Control :—

(a) A detailed specification shall be laid down by the manufacturer to safeguard the product from adverse effects of weather conditions.

(b) The product shall be well preserved both during storage and transit.

(v) Metrological control : Gauges and instruments used in the production and inspection shall be periodically checked or calibrated and records shall be maintained in the form of history cards by the manufacturer.

(vi) Packing control : The manufacturer shall lay down a detailed packing specification for export packages and shall strictly adhere to the same.

(2) Inspection :—The inspection of aluminium utensils meant for export shall be done by drawing samples from the consignments for carrying out examination and testing of the same with a view to see that the consignment conforms to the standard specifications recognized by the Central Government under section 6 of the Act.

4. Basis of inspection : Inspection of aluminium utensils intended for export shall be carried out with a view to see that the same conform to the specifications recognized by the Central Government under section 6 of the Act.

either

(a) by ensuring that during the process of manufacture the quality control drills as specified in sub-rule (1) of rule 3 have been exercised, or

(b) on the basis of inspection carried out in accordance with sub-rule (2) of rule 3.

or

(c) by both

5. Procedure of inspection : (1) (a) Any exporter intending to export a consignment of aluminium utensils shall give an intimation in writing to any one of the agencies of his intention so to do, and submit, alongwith such intimation a declaration, either that the consignment of aluminium utensils has been or is being manufactured by exercising quality control measures as per controls referred to under sub-rule (1) of rule 3 and that the consignment conforms to the standard specifications recognized for the purpose ; or, of the specifications stipulated in the export contract giving details of all the technical characteristics to enable the agency to carry out inspection in accordance with sub-rule (2) of rule 3.

(b) The exporter shall at the same time endorse a copy of such intimation to the nearest office of the Council. The addresses of the Council offices are as under :—

Head Office.—Export Inspection Council 'World Trade Centre' (7th Floor) 14/1B, Ezra Street, Calcutta-700001.

Regional Offices.—(i) Export Inspection Council, Aman Chambers (4th Floor), 113, M. Karve Road Bombay-400004.

(ii) Export Inspection Council, Manohar Buildings, Mahatma Gandhi Road, Ernakulam, Cochin-682011.

(iii) Export Inspection Council, Municipal Market Building, 3, Saraswati Marg, Karol Bagh, New Delhi-110005.

(2) The exporter shall also furnish to the Agency the identification marks applied on the consignment.

(3) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall reach the office of the agency not less than seven days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises or exporter's premises.

(4) (a) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (1), the agency, on satisfying itself on the basis of inspection carried out as provided for under rule 4 and the instruction, if any, issued by the council in this regard, that the consignment has been manufactured according to the standard specifications applicable to it, within seven days shall issue a certificate declaring the consignment of aluminium utensils as exportworthy : provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of seven days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter alongwith the reasons therefore.

(b) Except in cases where the exporter is himself the manufacturer of the consignment of aluminium utensils and the inspection is carried out according to the provisions of sub-clauses (a) or (c) of rule 4, in all other cases, after completion of inspection, the Agency shall immediately seal the packages of the consignment in a manner so as to ensure that the sealed goods cannot be tampered with. In case of rejection of the consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the agency. In such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer an appeal against the rejection.

6. Place of inspection : Inspection of aluminium utensils for the purpose of these rules shall be carried out :

(a) at the premises of the manufacturer, or

(b) at the premises at which the consignment of aluminium utensils is offered for inspection by the exporter, provided adequate facilities for the purpose of inspection and testing exist therein.

7. Inspection fee : A fee at the rate of fifty paise for every one hundred rupees of the free on board value of each consignment subject to a minimum of rupees fifty for each consignment shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee under these rules.

8. Appeal : (1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule 5, may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal, prefer an appeal to an appellate panel consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two thirds of the total membership of the panel shall consist of non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

ANNEXURE II

[See sub-paragraph (3) of paragraph 1]

Minimum Specification for Aluminimum Utensils

1.0 MATERIAL :

1.1 Aluminium content of wrought or cast aluminium utensils shall be not less than 99.0 per cent.

1.2 Chemical composition for wrought or cast aluminium alloy utensils shall be as agreed upon in the export contract between the foreign buyer and the exporter. In the absence of any such specific stipulation, the material shall conform to the latest issue of any national standard.

1.3 The thickness of the utensils shall be subject to agreement between the foreign buyer and the exporter.

2.0 SHAPES AND DIMENSIONS :

The shapes and dimensions of utensils shall be subject to agreement between the foreign buyer and the exporter. The following tolerances shall be applicable for the dimensions :—

Over	Upto and incluniug	Tolerance
mm	mm	mm
—	30	±1
30	100	±2
100	200	±3
200	—	±5

3.0 WORKMANSHIP AND FINISH :

Edges of the utensils shall not be left sharp. They shall be finished bright all over. Finished utensils shall be free from cracks, wrinkles, spills, distortion, dents, soratches, pittings, deep tool marks and other surface defects.

4.0 TEST :

4.1 Water leakage test—Utensils shall not leak when filled with water to the brim.

4.2 Bend Test :—A sample of material used for wrought aluminium utensil shall be bent through an angle of 180° and hammered close, whereupon the sample shall not fracture or show signs of cracking. In cases where the condition is specifically stipulated, bend test shall be done in accordance with the provisions of the latest version of any national standard. No bend test shall be applicable for cast utensil and wrought utensils having a thickness of sheet greater than 2.6 mm (12 SWG).

4.3 Lead and bismuth contest test :— Lead and bismuth contents of the material used for manufacture of the utensils shall not exceed 0.05 per cent each.

4.4 Anodic coating thickness test :— Anodic coating thickness on the utensil when determined by a standard stripping method according to IS 1868 : 1968 (or its latest version) shall be not less than 5 microns. This test shall be applicable only for anodized utensils.

5.0 MARKING :

Unless otherwise stipulated by the foreign buyer, utensils shall be legibly marked at the bottom with the manufacturer's name, trade mark or identification mark in such a manner as to ensure that the impression of the marking shall not show up on the other side.

6.0 PACKING :

6.1 The package shall be well finished and have a good appearance.

6.2 Inner contents of the package shall be so packed as to withstand the following tests—

6.2.1. Drop test (for head loads upto 37 kgs gross weight only) one package shall be dropped from a height of 190 cm once on the largest flat surface, once on the largest edge and once on any corner of its own.

6.2.2. Rolling test (upto 500 kgs. gross weight only) One package shall be subjected to rolling on its sides either six metres forward and six metres backward or twelve metres in one direction only.

6.2.3. Water spray test (for each design of package) The package shall be exposed against a water spray equivalent to a sudden monsoon shower for five minutes.

7.0 Sampling and Criteria for Conformity :

7.1. Sampling for inspection of each consignment and the criteria for conformity shall be in accordance with the Table given below.

7.2. In any consignment, all the utensils of the same material and design irrespective of size shall be grouped together to constitute a lot/except for destructive test where all the types and sizes manufactured from the same batch of material shall be grouped together to constitute a lot.

TABLE

Lot Size	Sample Size: For clauses 2.0, 3.0, 5.0, 6.0 and sub-clause 4.1 A	Sample Size: For sub-clauses 4.2, 4.3 and 4.4 B	Permissible Number of Defectives: For A of Col (2)	Permissible Number of Defectives: For B of Col (2)
Upto 15	2	1	0	NIL
16 to 25	3	1	0	
26 to 100	5	1	0	
101 to 150	8	2	0	
151 to 300	13	2	0	
301 to 500	20	3	1	
501 to 1000	32	3	2	
1001 to 3000	50	4	3	
3001 and above	80	5	5	

SCHEDULE

(See Rule 3)

Sl. No.	Test/Inspection Characteristic	Requirements	No. of samples to be tested	Lot size/frequency	Remarks
1.	Material (i) Chemical composition (ii) Mechanical properties	As per standard specifications.	One	For each cast/heat of raw material.	Whenever supported by producer's certificates, these characteristics shall be verified at least once in five consignment.
2.	Process Control:				
	(i) Workmanship and finish	-do-	Each	Each batch of production of one type & size.	
	(ii) Dimensions	-do-	One	First-off sample and then every fifty Nos. of each type and size.	
3.	Anodizing, if applicable:				
	(a) Finish	-do-	Each	Each batch of production of one type and size.	
	(b) Thickness of coating	-do-	One	-do-	
	(c) Any other test	-do-	One	-do-	
4.	Packing Control:				
	(i) Drop test	-do-	One	Each consignment.	
	(ii) Rolling test	-do-	One	-do-	
	(iii) Water spraying test	-do-	One	Each design of package.	

[No. 6(3)/79-EI & EP]

का०आ० 2473.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए यह आवश्यक तथा समीचीन है कि विद्युत मोटरों तथा जनित्रों को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त उपनियम के अनुसरण में उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहे तो वह उन्हें राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद मेवर्ल्ड ट्रेड सैन्टर" (8 वी मंजिल) 14/1 बी० एजरा स्ट्रीट कलकत्ता- 700001 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि विद्युत मोटरें तथा जनित्र निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे।

(2) इस आदेश के उपाबंध 1 में दिए गए विद्युत मोटरों तथा जनित्रों का निर्यात क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण नियम, 1979 के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को

क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व ऐसे विद्युत मोटरों तथा जनित्रों पर लागू होगा।

(3) (क) भारतीय या किसी अन्य राष्ट्रीय विनिर्देशों को अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग की सिफारिशों विनिर्देशों को किसी भी देश के सरकारी विभाग या जन उपयोगी सेवाओं द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों को विद्युत मोटरों तथा जनित्रों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है,

और

(ख) उन विनिर्देशों को जो खंड (क) के अंतर्गत नहीं आते हैं किन्तु निर्यातकर्ता द्वारा घोषित ऐसे विनिर्देशों की परीक्षा और अनुमोदन इस प्रयोजन के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अनुमोदित है, ऐसे विद्युत मोटरों तथा जनित्रों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है।

(4) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे किसी विद्युत मोटर तथा जनित्र के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरणों में से किसी एक के द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि विद्युत मोटरों तथा जनित्रों के परेषण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं तथा निर्यात योग्य हैं।

3 इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भूमि समुद्री या वायु मार्ग द्वारा विद्युत मोटरों तथा जनित्रों के वास्तविक नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी।

4. इस आदेश में "विद्युत मोटरों" से ऐसी मशीन अभिप्रेत है जो विद्युत ऊर्जा को मशीनी शक्ति में संपरिवर्तित करती है तथा "जनित्रों" से वह मशीन अभिप्रेत है जो यांत्रिक शक्ति को विद्युत ऊर्जा में संपरिवर्तित करती है। इसमें बिजली के पंखे, आटोमोबाइल स्टार्टर तथा डायनेमों, साइकिल डायनेमों तथा मोटरें, जो बिजली तथा इलक्ट्रोनिक घरेलू उपकरणों तथा खिलौनों में प्रयोग किए जाते हैं, सम्मिलित नहीं होंगे।

उपाबंध 1

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप।

1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मोटरों तथा जनित्रों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है।

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है।

(ग) "विद्युत मोटरों" से ऐसी मशीन अभिप्रेत होगी जो विद्युत ऊर्जा को मशीनी शक्ति में संपरिवर्तित करने में समर्थ हो तथा जनित्रों से वह मशीन अभिप्रेत होगी जो यांत्रिकी शक्ति को विद्युत ऊर्जा में संपरिवर्तित करने में समर्थ हो। इसमें बिजली के पंखे, आटोमोबाइल स्टार्टर तथा डायनेमों, साइकिल डायनेमों तथा मोटरें, जो बिजली तथा इलक्ट्रोनिक घरेलू उपकरणों तथा खिलौनों में प्रयोग किए जाते हों सम्मिलित नहीं होंगे।

3. क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण:— (1) क्वालिटी नियंत्रण:—निर्यात के लिए आशयित विद्युत मोटरों तथा जनित्रों का क्वालिटी नियंत्रण यह देखने की दृष्टि से किया जाएगा कि क्या वह, उससे उपबंधित अनुसूची में दिए गए नियंत्रण के स्तरों के साथ विनिर्माण के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है, अर्थात् :—

(i) खरीदी गई सामग्री तथा घटक नियंत्रण :—

(क) प्रयोग की जाने वाली सामग्री या घटकों के गुण धर्मों को समाविष्ट करते हुए विनिर्माता क्रय विनिर्देश अधिकथित करेगा तथा आने वाले लाटों की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए उसके पास निरीक्षण या परीक्षण के पर्याप्त साधन होंगे।

(ख) स्वीकृत परेषणों के साथ क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं की पुष्टि करते हुए प्रदाय-कर्ता का या तो परीक्षण या निरीक्षण प्रमाण-पत्र होगा, इस दशा में उक्त परीक्षण या निरीक्षण प्रमाण-पत्रों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए क्रेता द्वारा किसी विशिष्ट प्रदायकर्ता के लिए यदा कदा जांच (अर्थात एक ही माल के एक ही प्रदायकर्ता के लिए वर्ष की प्रत्येक तिमाही में एक बार) की जाएगी या खरीदी गई सामग्री या घटकों का नियमित निरीक्षण और परीक्षण या तो कारखाने के भीतर प्रयोगशाला में या किसी अन्य प्रयोगशाला या परीक्षण गृह में किया जाएगा।

(ग) किए जाने वाले परीक्षण या निरीक्षण के लिए नमूना लेना लेखबद्ध अपेक्षण पर आधारित होगा।

(घ) निरीक्षण या परीक्षण किए जाने के पश्चात् स्वीकृत तथा अस्वीकृत सामग्री या घटकों को पृथक करने के लिए तथा अस्वीकृत माल या घटकों के व्ययन के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी।

(ङ) ऊपर विनिर्दिष्ट नियंत्रण के संबंध में यथोचित अभिलेख विनिर्माता द्वारा नियमित तथा व्यवस्थित ढंग से रखे जाएंगे।

(ii) प्रक्रिया नियंत्रण :—

(क) विनिर्माता विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित करेगा।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देशों में अधिकथित प्रक्रियाओं का नियंत्रण करने के लिए यथोचित उपस्कर, यंत्र समुच्चय और सुविधाएं होंगी।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणों के सत्यापन की संभावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता यथोचित अभिलेखों को रखेगा।

(iii) उत्पाद नियंत्रण :—

(क) यह परीक्षण करने के लिए कि उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है या नहीं विनिर्माता के पास या तो स्वयं अपनी यथोचित परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हों, होंगी।

(ख) परीक्षण के लिए नमूना लेना (जहां की अपेक्षित हो) लेखबद्ध अपेक्षण पर आधारित होगा।

(ग) किए गए परीक्षणों के संबंध में विनिर्माता द्वारा यथोचित अभिलेख नियमित तथा व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे।

(4) परीक्षण नियंत्रण :—

(क) विनिर्माता मौसमी दशाओं के प्रतिकूल प्रभावों से उत्पाद को सुरक्षित करने के लिए ब्यौरेवार विनिर्देश अधिकथित करेगा ।

(ख) भंडारकरण तथा अभिवहन, दोनों के दौरान उत्पाद अच्छी तरह से परिरक्षित किया जाएगा ।

(5) मापकीय नियंत्रण :—

उत्पादन तथा निरीक्षण में प्रयुक्त प्रमापकों और उपकरणों की कालिक जांच या अंशांकन किया जाएगा और अभिलेख विनिर्माता द्वारा बनाए रखे जाएंगे ।

(1) पैकिंग नियंत्रण :—

विनिर्माता निर्यात किए जाने वाले पैकजों के लिए ब्यौरेवार पैकिंग विनिर्देश अधिकथित करेगा तथा उनका पूर्णतया पालन करेगा ।

(2) निरीक्षण :— निर्यात के लिए आशयित विद्युत मोटरों तथा जनित्रों का निरीक्षण इस दृष्टि से परीक्षा और परीक्षण करने के लिए किया जाएगा कि परेषण अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है ।

4. निरीक्षण का आधार :—निर्यात के लिए आशयित विद्युत मोटरों तथा जनित्रों का निरीक्षण यह देखने की दृष्टि से कि वे अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निर्देशों के अनुरूप हैं,

या तो

(क) यह सुनिश्चित करके किया जाएगा कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान नियम 3 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण अभ्यासों का प्रयोग किया गया है,

या

(ख) नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसार किए गए निरीक्षण के आधार पर किया जाएगा ।

या

(ग) दोनों द्वारा किया जाएगा ।

5. निरीक्षण की प्रक्रिया :—

(1) (क) विद्युत मोटरों तथा जनित्रों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता अपने ऐसा करने के अपने आशय की लिखित संसूचना किसी भी एक अभिकरण को देगा तथा ऐसी संसूचना के साथ :—

(क) या तो यह घोषणा देगा कि विद्युत मोटरों तथा जनित्रों का परेषण नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियंत्रणों के अनुसार क्वालिटी उपायों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं या नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसार निरीक्षण करने के लिए अभिकरण को समर्थ बनाने के लिए सभी तकनीकी विशेषताओं के ब्यौरे देते हुए, निर्यात संविदा में कथित विनिर्देशों की घोषणा देगा ।

(ख) निर्यातकर्ता उसी समय ऐसी सूचना की एक प्रति परिषद् के निकटतम कार्यालय को देगा । परिषद् के कार्यालयों के पते निम्नलिखित हैं :—

मुख्य कार्यालय	निर्यात निरीक्षण परिषद्, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर (8वी मंजिल), 14/1बी० एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता, 700001
प्रादेशिक कार्यालय	(1) निर्यात निरीक्षण परिषद् अमन चैम्बर्स (5वी मंजिल) 113, महर्षि कार्वे रोड, बम्बई, 400004
	(2) निर्यात निरीक्षण परिषद्, मनोहर बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन 682011
	(3) निर्यात निरीक्षण परिषद् मुनिसिपल मार्केट बिल्डिंग 3, सरस्वती मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली—110005

(2) निर्यातकर्ता अभिकरण को परेषण पर लगाए गए पहचान चिह्न भी देगा ।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा निर्यातकर्ता के परिसर से या विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम-से-कम सात दिन पहले अभिकरण के कार्यालय में पहुंचेगी ।

(4) (क) उपनियम (1) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर अभिकरण नियम 4 और इस निमित्त परिषद् द्वारा जारी किए गए अनुदेश, यदि कोई हो, के अधीन यथा उपबंधित रूप से किए गए निरीक्षण के आधार पर अपने यह समाधान कर लेने पर कि परेषण का विनिर्माण इस पर लागू मानक विनिर्देशों के अनुसार किया गया है सात दिनों के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि विद्युत मोटरों तथा जनित्रों का परेषण निर्यात योग्य है ।

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं हुआ है वहां वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करेगा और ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित निर्यातकर्ता को भेजेगा ।

(ख) सिवाय ऐसे मामलों में जहां निर्यातकर्ता स्वयं विद्युत मोटरों तथा जनित्रों के परेषण का विनिर्माता हो तथा निरीक्षण नियम 4 के उपबंध (क) या (ग) के उपबंधों के अनुसार किया गया है अन्य सभी मामलों में निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात् तत्काल अभिकरण परेषण के पैकेजों को इस ढंग से सीलबंद करेगा कि यह सुनिश्चित हो सके कि सीलबंद माल के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है । परेषण के अस्वीकृत किए जाने की दशा में, यदि निर्यातकर्ता चाहे तो परेषण अभिकरण द्वारा सील बंद नहीं किया जा सकता है । तथापि ऐसे मामलों में निर्यातकर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा ।

6. निरीक्षण का स्थान :—इन नियमों के प्रयोजनों के लिए विद्युत मोटरों तथा जनित्रों का निरीक्षण :—

(क) विनिर्माता के परिसर पर,

या

(ख) उस परिसर पर किया जाएगा जहां निर्यातकर्ता विद्युत मोटरों तथा जनित्रों का परेषण निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा, परन्तु यह तब जब कि वहां निरीक्षण के प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों ।

7. निरीक्षण फीस :—

(1) नियम 4(क) तथा 4(ग) में दिए गए आधार पर किए गए निरीक्षण की दशा में प्रत्येक परेषण के लिए न्यूनतम एक सौ रुपये के अधीन रहते हुए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 0.2 प्रतिशत ।

(2) नियम 4(ख) में दिए गए आधार पर किए गए निरीक्षण की दशा में प्रत्येक परेषण के लिए न्यूनतम एक सौ रुपये के अधीन रहते हुए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 0.5 प्रतिशत ।

8. अपील :—

(1) नियम 5 के उपनियम (4) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय पैनल को अपील कर सकेगा, जिसमें कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे ।

(2) पैनल की कुल संख्या के कम से कम तो तिहाई गैर सरकारी सदस्य होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी ।

अनुसूची I

(नियम 3 देखिए)

नियंत्रण की परखें

क्रम०सं०	निरीक्षण/परीक्षण की विशेषताएं	अपेक्षाएं	नमूना आकार	लाट आकार
1	2	3	4	5
1.	खरीदी गई सामग्री तथा घटक			
	(क) चाक्षुष निरीक्षण कारीगरी तथा फिनिश सहित	उस प्रयोजन के लिए मान्यता-प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित अन्वेषण के आधार पर निश्चित किया जाएगा	—
	(ख) सहायता सहित विमाएं	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—
	(1) क्रांतिक	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—
	(2) अन्य	—यथोक्त—	अभिलिखित अन्वेषण के आधार पर निश्चित किया जाएगा।	प्रत्येक लाट
	(ग) घटकों के लिए विद्युत परीक्षण	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
	(घ) कोई अन्य अपेक्षा	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
2.	प्रेरणी मोटर तथा जनित्र			
	(i) नैमिक परीक्षण			
	(क) रोधन सहायता परीक्षण (उच्च वोल्टता परीक्षण से पहले)	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
	(ख) उच्च वोल्टता परीक्षण	इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुसार		—
	(ग) वोल्टता तथा तीन फेजों में मोटर की शून्य भारचालूता तथा धारा का पठन	—वही—	—वही—	—
	(घ) केवल पिंजरी मोटरों के लिए उपयुक्त वोल्टता पर ताला बंद रोटर परख	—वही—	—वही—	—
	(ङ) मोटर पर लागू होने वाली लाइन वोल्टता की 1/3 गति के साथ घूर्णन का प्रत्येक दशा में बिना भार के पूर्ण गति चलने वाली मोटर की क्षमता को जांचने के लिए शून्य भार पर घटाई हुई वोल्टता चालूता परख	—वही—	—वही—	—
	(च) खुला परिपथ वोल्टता अनुपात (केवल फिसलने वाली मोटर के लिए)	इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक मान्य मानक विनिर्देशों के अनुसार		—
	(ii) प्रकार परखें			
	(क) फिसलने वाली मोटर पर स्टार्टर प्रतिरोधन का तथा रोटार प्रति रोध का माप	—वही—	अभिलिखित अन्वेषण के आधार पर निश्चित किया जाएगा	—
	(ख) वोल्टता, धारा, शक्ति, बल तथा फिसलन का संपूर्ण भार पठन	—वही—	—वही—	—
	(ग) ताप वृद्धि	—वही—	—वही—	—
	(घ) अस्थायी अति भार परख	—वही—	—वही—	—
3.	तुल्यकाली मोटर तथा जनित्र			
	(i) दैनिक परखें		प्रत्येक	—
	(क) प्रतिरोधन का माप	इस प्रयोजन के लिए मान्य मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक	—
	(ख) विद्युत रोधी प्रतिरोध परख	—वही—	—वही—	—
	(ग) फैज अनुक्रम परख	—वही—	—वही—	—
	(घ) नियमन परख (केवल उत्पादकों के लिए)	—वही—	—वही—	—
	(ङ) खुले परिपथ विशेषता का माप (केवल उत्पादक के लिए)	—वही—	—वही—	—
	(च) लघु परिपथ विशेषता का माप (केवल उत्पाद के लिए)	—वही—	—वही—	—
	(छ) उच्च वोल्टता परख	—वही—	—वही—	—

1	2	3	4	5
	(ज) 1000 किलो वाट से अधिक की मशीन के लिए सहभीय धारा का परिमाप	इस प्रयोजन के लिए मान्य मानक—प्रत्येक— विनिर्देशों के अनुसार		—
	(झ) अंत परिपथ कूलिंग के लिए प्रशीतकों पर दाब परख	—वही—	—वही—	—
	(2) प्रकार परखें			
	(क) क्षरण प्रतिघात पोटियार प्रतिघात के परिमाप (केवल उत्पादकों के लिए)	—वही—	अभिलिखित अन्वेषण के आधार पर निश्चित किया जाएगा	—
	(ख) क्षमता परख	—वही—	—वही—	—
	(ग) ताप वृद्धि परख	—वही—	—वही—	—
	(घ) अस्थायी अति भार परख	—वही—	—वही—	—
	(ङ) अति गति परख	—वही—	—वही—	—
	(च) प्रारम्भिक धारा तथा टार्क परख (तुल्यकाली मोटरों के लिए)	—वही—	—वही—	—
	(छ) शिरानालाभ से वोल्टता तरंग के विचलन का वृद्धिकरण (केवल उत्पादकों के लिए)	—वही—	—वही—	—
	(ज) लघु परिपथ सहायता तथा एक समान समय तथा प्रतिघात का परिमाप (केवल 1000 किलो वाट से अधिक उत्पादकों के लिए)	—वही—	—वही—	—
4. डी०सी० मोटर तथा उत्पादक दैनिक परखें				
	(क) प्रतिरोधकों के परिमाप	इस प्रयोजन के लिए मान्य मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक	—
	(ख) विद्युत रोधी प्रतिरोध का परिमाप	—वही—	—वही—	—
	(ग) घूर्णन की दशा में निश्चित करने की परख	—वही—	—वही—	—
	(घ) नियमन परख (केवल उत्पादकों के लिए)	—वही—	—वही—	—
	(ङ) खुले परिपथ विशेषता का परिमाप	—वही—	—वही—	—
	(च) उच्च वोल्टता परख	—वही—	—वही—	—
	(छ) संचरण परख	—वही—	—वही—	—
	(झ) कोई अन्य परख	क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट के अनुसार या राष्ट्रीय मानकों में विनिर्दिष्टों के अनुसार	—वही—	—
प्रकार परखें				
	(क) ताप वृद्धि परख	इस प्रयोजन के लिए मान्य मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित अन्वेषण के आधार पर किया जाएगा	—
	(ख) कार्यक्षमता परख	—वही—	—वही—	—
	(ग) 1000कि०वाट तक उत्पादन वाली मशीनों के लिए भार विशेषता का परिमाप	—वही—	—वही—	—
	(घ) अस्थायी अति भार परख	—वही—	—वही—	—
	(ङ) डी०सी० मोटर के लिए प्रारम्भिक टार्क परख	—वही—	—वही—	—
	(च) दिष्ट धारा उत्तेजकों के लिए नाम मात्र का उत्तेजक, प्रतिक्रिया	—वही—	—वही—	—
	(छ) कोई अन्य परख	क्रेता द्वारा अभिलिखत के अनुसार या राष्ट्रीय मानकों के अनुसार	—वही—	—
5. पैकिंग				
	(क) रूप	—वही—	प्रत्येक	—
	(ख) ड्राप परख	—वही—	एक संख्या	प्रत्येक परेषण
	(ग) रोलिंग परख	—वही—	—वही—	—
	(घ) जल फुहार परख	—वही—	एक संख्या	प्रत्येक डिजाइन

*** पैकेज की फिनिश अच्छी तरह की जाएगी तथा देखने में सुन्दर होगा।

**** पैकेज यह सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार का होगा कि उसमें रखा माल नीचे दी गयी पात परख, रोलिंग परख तथा जल फुहार परख को सहन कर सकेंगे ।

पात परख :— (केवल 37 कि०ग्रा० तक के भार तक निर्धारित करने के लिए) 150 सें०मी० की ऊंचाई से गिराए जाने वाले पैकेज एक बार बड़ी समतल सतह पर एक बार सबसे लम्बे किनारे पर और एक बार उसके किसी भी किनारे पर गिराया जाएगा ।

रोलिंग परख :— (केवल 500 कि०ग्रा० तक के भार तक निर्धारित करने के लिए) रोलिंग करने वाले पैकेज इसके किसी भी और 6 मीटर आगे तरफ तथा 6 मीटर पीछे की तरफ या बारह मीटर एक दशा रोल किए जाएंगे ।

जल फुहार :—जल फुहार के लिए खोलने वाला एक मिनट के लिए सामान्य या आकस्मिकता के समतुल्य होगा ।

अनुसूची II

(नियम 4 देखिए)

परेषणानुसार निरीक्षण की दशा में अनुरूपता की कसौटी तथा नमूना लेखा

सारणी—I

क्र० सं०	विशेषताएं	लॉट आकार	परख किए जाने वाले नमूनों की संख्या
1.	सभी विमीय तथा चाक्षुष जांच (बाह्य)	एक ही प्रकार तथा वर के मोटर तथा उत्पादक	नमूना सारणी II के अनुसार
2.	दैनिक परख	—यथोक्त—	—यथोक्त—
3.	प्रकार परख	—यथोक्त—	—यथोक्त—

सारणी—II

क्र०सं०	एक ही प्रकार तथा वर के उत्पादकों की संख्या	परख किए जाने वाले नमूनों की संख्या	अनुमेय दोषों की संख्या
1.	8 तक	2	शून्य
2.	9 से 15 तक	3	शून्य
3.	16 से 25 तक	5	शून्य
4.	26 से 50 तक	8	शून्य
5.	51 से 100 तक	13	शून्य
6	101 से अधिक	20	शून्य

[सं० 6(36)/76-वि०नि० तथा नि०व०]

के० वी० बाल सुब्रह्मण्यम, उप सचिव

S.O. 2473.—Whereas the Central Government is of opinion that, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient so to do for the development of export trade of India that electric motors and generators shall be subject to quality control and inspection prior to export;

And, whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule II of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964.

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objction or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within forty five days of the date of pubication of this order in the Official Gazette to the Export Inspection Council, World Trade Centre (7th floor), 14/1B, Ezra Street, Calcutta-700001

PROPOSALS

(1) To notify that electric motors and generators shall be subject to quality control and inspection prior to export;—

(2) To specify the type of inspection in accordance with the draft Export of Electric Motors and generators (Quality Control and Inspection) Rules, 1979 set out in Annexure-I to this order as the type of quality control and inspection which would be applied to such electric motors and generators prior to export; recognises :—

(3) (a) Indian or any other national specifications, International electrotechnical commission recommendations/specifications approved by a government department or public utility services of country as the standard specifications for electric motors and generators.

(b) the specifications and which do not fall under clause (a) but are approved by a panel of experts appointed by the Export Inspection Council for the purpose of examining and approving such specifications declared by the exporter as the standard specification for such electric motors and generators.

(4) To prohibit the export in the course of international trade of any such electric motors and generators unless the same are accompanies by a certificate issued by any one of the agencies established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the consignments of electric motors and generators satisfy the conditions relating to quality control and inspection and are exportworthy.

3. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of bonafide samples of electric motors and generators to prospective buyers.

4. In this order "electric motors" shall mean a machine which is capable of converting electric energy into mechanical power and "generators" shall mean a machine capable of converting mechanical power to electric energy this shall not included electric fan, automobile starter and dynamoes bicycle dynamoes and motors to be used in electrical electronic domestic appliances and toys.

ANNEXURE I

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of electric motors and generators (Quality Control and Inspection) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of publication in Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requries :

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(b) "agency" means any one of the agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under Section 7 of the Act.

(c) "electric motors" shall mean a machine which is capable of converting electric energy into mechanical power.

(d) "generators" shall mean a machine capable of converting mechanical power to electrical energy.

This shall not include electric fans, automobile starters and dynamoes, bicycle dynamoes and motors to be used in electrical & electronic appliances and toys.

3. Quality control and inspection.—Quality Control.—The Quality Control of the electric motors and generators intended for export shall be done with a view to see that the same conform to the specifications recognized by the Central Government under section 6 of the Act by effecting the following controls at different stages of manufacture together with the levels of control as given in the schedule annexed hereto namely :—

(i) Bough out materials and components control :—

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used and shall have adequate means of inspection or testing to ensure conformity of the incoming lots.

(b) The accepted consignments shall be either accompanied by a supplier's test or inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specification, in which case occasional checks (that is to say once in each quarter of the year for the same supplier of the same material) shall be conducted by the manufacturer for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test or inspection certificates, or the purchased materials or components shall be regularly inspected or tested either in a laboratory in the factory or in some other laboratory or test house.

(c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be based on a recorded investigation.

(d) After the inspection or test is carried out, systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials or components and in disposal of rejected materials or components.

(e) Adequate records in respect of the above mentioned controls shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(ii) Process Control :—

(a) Detailed process specification shall be laid down by the manufacturer for different processes of manufacture.

(b) Equipments, instrumentation and facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process specifications.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacturer to ensure the possibility of verifying the controls exercised during the process of manufacture.

(ii) Product Control :—

(a) The manufacturer shall either have his own adequate testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the specification recognised under section 6 of the Act.

(b) Sampling (wherever required) for testing shall be based on a recorded investigation.

(c) Adequate records in respect of tests carried out shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(iv) Preservation Control :—

(a) A detailed specification shall be laid down by the manufacturer to safeguard the product from adverse effects of weather conditions.

(b) The product shall be well preserved both during storage and transit.

(v) Metrological Control :—

Gauges and instruments used in the production and inspection shall be periodically checked or calibrated and records shall be maintained in the form of history cards by the manufacturer.

(vi) Packing Control :—

The manufacturer shall lay down a detailed packing specification for export packages and shall strictly adhere to the same.

3. Inspection.—The inspection of electric motors and generators meant for export shall be done by drawing samples as per schedule II annexured here to form the consignment for carrying but examination and testing of the same with a view to see that the consignment conforms to the standard specification recognized by the Central Government under section 6 of the Act.

4. Basis of inspection.—Inspection of electric motors and generators intended for export shall be carried out with a view to see that the same conform to the specification recognized by the Central Government under section 6 of the Act.

either

(a) by ensuring that during the process of manufacture the quality control drills as specified in sub-rule (1) of rule 3 have been exercised.

or

(b) on the basis of inspection carried out in accordance with sub-rule (2) of rule 3.

or

(c) by both.

5. Procedure of inspection.—(1) (a) Any exporter intending to export a consignment of electric motors and generators shall give an intimation in writing to any one of the agencies of his intention so to do, and submit, along with such intimation a declaration either that the consignment of electric motors and generators has been or is being manufactured by exercising quality control measures as per controls referred to under sub-rule (1) of rule 3 and that the consignment conforms to the standard specifications recognized for the purpose or, of the specification stipulated in the export contract giving details of all the technical characteristics to enable the agency to carry out inspection in accordance with sub-rule (2) of rule 3.

(b) The exporter shall at the same time endorse a copy of such intimation to the nearest office of the Council. The addresses of the Council offices are as under :—

Head Office :

Export Inspection Council
'World Trade Centre' (7th floor),
14/1B, Ezra Street,
Calcutta-700 001.

Regional Offices :—

(i) Export Inspection Council,
Aman Chambers, (4th floor),
113, M. Karve Road,
Bombay-400 004.

(ii) Export Inspection Council,
Manohar Buildings,
Mahatma Gandhi Road,
Ernakulam, Cochin-682 011.

(iii) Export Inspection Council,
Municipal Market Building,
3, Saraswati Marg, Karol Bagh,
New Delhi-110 005.

(2) The exporter shall also furnish to the Agency the identification marks applied on the consignment.

(3) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall reach the office of the agency not less than seven days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's promises or exporter's premises.

(4) (a) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (1) the agency, on satisfying itself, on the basis of inspection carried out as provided for under rule 4 and the instruction, if any issued by the Council in this regard, that the consignment has been manufactured according to the standard specifications application to it within seven days shall issue a certificate declaring the consignment of electric motors and generators as exportworthy ;

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of seven days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

(b) Except in cases where the exporter is himself the manufacturer of the consignment of electric motors and generators and the inspection is carried out according to the provisions of sub-clauses (a) or (c) of rule 4, in all other cases, after completion of inspection, the Agency shall immediately seal the packages of the consignment in a manner so as to ensure that the sealed goods cannot be tampered with. In case of rejection of the consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the agency. In such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer an appeal against the rejection.

6. Place of inspection.—Inspection of electric motors and generators for the purpose of these rules shall be carried out :

(a) at the premises of the manufacturer

or

(b) at the premises at which the consignment of electric motors and generators, is offered for inspection by the exporter, provided adequate facilities for the purpose of inspection and testing exist therein.

7. Inspection fee.—0.2 per cent on Free on board value subject to a minimum of rupees one hundred for each consignment in case the inspection is carried out on the basis given in rule 4(a) and 4(c)

(ii) 0.5 per cent of free on board value subject to a minimum of rupees one hundred for each consignment in case the inspection is carried out on the basis given in rule 4(b).

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule 5, may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal prefer an appeal to an appellate panel consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two thirds of the total membership of the panel shall consist of non-officials.

(3) The quorum for the Panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

SCHEDULE I

(See Rule 3)

The Test of Control

Sl. No.	Particulars of Inspection/test	Requirement	Sample size	Lot size
1.	Bought out materials and components:			
	(a) Visual Inspection (including workmansip and finish).	As per standard specification recognized for the purpose.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—
	(b) Dimensions with tolerances:			
	(1) Critical	-do-	-do-	
	(2) Others	-do-	To be fixed on the basis of recorded investigation.	Each lot.
	(c) Electrical tests for components	-do-	-do-	-do-
	(d) Any other requirements	-do-	-do-	-do-
2.	Induction Motors and Generators :			
	(i) Routine tests:			
	(a) Insulation resistance test (before high voltage test).	-do-	Each	—
	(b) High voltage test	As per standard specification recognized for the purpose.	each	—
	(c) No load running of motor and reading of current in the three phases and voltage.	-do-	-do-	—
	(d) Locked rotor test at suitable voltage for squirrel cage motors only.	-do-	-do-	—
	(e) Reduced voltage running up test at no load to check the ability of motors to run upto full speed on no load in each direction of rotation with 1/53 of rates line voltage applied to motor.	-do-	-do-	—

1	2	3	4	5
2.	(i) Open Circuit voltage ratio (for slip ring motors only).	As per standard specification recognized for the purpose.	Each	—
	(ii) Type tests			
	(a) Measurements of stator resistance and rotar resistance on slip ring motors.	-do-	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—
	(b) Full load reading of voltage current power in put and slip.	-do-	-do-	—
	(c) Temperature rise	-do-	-do-	—
	(d) Momentary overload test	-do-	-do-	—
3.	Synchronous Motor and Generators:			
	(i) Routine tests:			
	(a) Measurements of resistance	As per standard specification recognized for the purpose.	Each	—
	(b) Insulation resistance test	-do-	-do-	—
	(c) Phase sequence test	-do-	-do-	—
	(d) Regulation test (for generator only).	-do-	-do-	—
	(e) Measurement of open-circuit characteristic (for generator only).	-do-	-do-	—
	(f) Measurement of short-circuit characteristic (for generator only).	-do-	-do-	—
	(g) High voltage test	-do-	-do-	—
	(h) Measurement of bearing current for machines above 1000 K.W.	-do-	-do-	—
	(i) Pressure test on coolers for closed circuit cooling.	-do-	-do-	—
	(ii) Type tests:			
	(a) Measurements of leakage reactance potior reactance (for generators only).	As per standard specification recognized for the purpose.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—
	(b) Efficiency tests	-do-	-do-	—
	(c) Temperature rise test	-do-	-do-	—
	(d) Momentary overload test	-do-	-do-	
	(e) Over speed test	-do-	-do-	—
	(f) Starting current and torque test (for synchronous motors).	-do-	-do-	
	(g) Determination of deviation voltage waves from sinusoidal (for generators only).	-do-	-do-	
	(h) Sort circuit with stand test and measurement of reactance and time constants (for Generators above 1000 K.W. only).	-do-	-do-	
4.	(i) D.C. Motor and Generators : Routine tests :			
	(a) Measurements of resistance	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	—
	(b) Measurement of insulation resistance.	-do-	-do-	—
	(c) Tst to determine the direction of rotation.	-do-	-do-	—
	(d) Regulation test (for Generators only).	-do-	-do-	—
	(e) Measurement of open circuit characteristic (for Generators only).	-do-	-do-	—
	(f) High voltage test	-do-	-do-	—
	(g) Commutation test	-do-	-do-	—
	(h) Any other test	As specified by the buyer or as specified in the National standard.	-do-	—

4. (i) Type Tests:			
(a) Temperature rise test	As per standard specification recognized for the purpose.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	
(b) Efficiency test	-do-	-do-	
(c) Measurement of load characteristic for machines having outputs upto 100 K.W.	-do-	-do-	
(d) Momentary overload test	-do-	-do-	
(e) Starting torque test for D C. Motors.	-do-	-do-	
Nominal exciter response for D.C. Exciters.	-do-	do-	
(g) Any other test	As specified by the buyer or as per National standard.	-do-	
5. Packaging			
*** (a) Appearance	-do-	Each.	
**** (b) Drop test	-do-	One number	Each consignment.
(c) Rolling test	-do-	-do-	-do-
(d) Water spraying test	-do-	One number	Each design.

*** The package shall be well finished and have a good appearance.

**** The package shall be such as to ensure that the inner contents shall withstand Drop Test, Rolling Test and Water Spraying Test as given below.

Drop Test: –(to be restricted to head loads only upto a weight of 37 Kg.) The package to be dropped from a heigt of 150cm once on the largest flat surface, once on the longest edge and once an any corner of its own.

Rolling Test:—(to be restricted to a weight of 500 Kg. only) The package to be subjected to rolling on its sides either six meters forward and six metres backward or twelve metres in one direction only.

Water Spraying Test:—The package to be allowed to be exposed against a water spray equivalent to a normal accidental shower for one minute.

SCHEDULE II

(See Rule 4)

Sampling and criteria of conformity in case of Consignmentwise Inspection

TABLE I

Characteristics	Lot Size	No. of Samples to be tested
1. All dimensional and visual check (external)	Motors and Generators of one type and rating.	As per the sampling Table II
2. Routine test	-do-	-do-
3. Type test	-do-	1

TABLE II

Sl. No.	No. of Motors and Generators of one type and rating	No. of samples to be tested	No. of Permissible defectives
1.	upto 8	2	Nil
2.	9 to 15	3	Nil
3.	16 to 25	5	Nil
4.	26 to 50	8	Nil
5.	51 to 100	13	Nil
6.	101 and above	20	Nil

[No. 6(36)/76-EI & EP]

K. V. BALASUBRAMANIAM, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979